सुविचार
एक शांत और स्थिर दिमाग जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है।
-गौतम बुद्ध

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Tuesday, 10 February 2026 ● Year : 05 ● Issue : 28 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Pati Patni Aur Woh Do Postponed...

फोटोन एक्सक्लूसिव... कांके थाने में दर्ज एक मामले को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद रांची एसएसपी ने लिया एक्शन

कांके थानेदार कर रहे लापरवाही, एक और विभागीय कार्यवाही शुरू

आईओ ने 11 महीनों में नहीं की कोई कार्रवाई, पूरी तरह ठप रखी जांच, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं

केस के फॉर्मर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर एएसआई संतोष कुमार पर भी गिरी गाज

SUHAIB ANSARI :
रांची के कांके थानेदार प्रकाश रजक लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। इनके खिलाफ एक और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कांके थाना में दर्ज एक मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद एसएसपी राकेश रंजन ने यह आदेश जारी किया है। थानेदार के अलावा केस के फॉर्मर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (आईओ) एएसआई संतोष कुमार पर भी गाज गिरी है। दरअसल, कांके थाना में दर्ज एक मामले की अनुसंधान प्रक्रिया में झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद रांची एसएसपी ने कांके थानेदार और आईओ के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश जारी किया है। इस केस में आईओ ने 11 महीनों में कोई कार्रवाई नहीं की और जांच पूरी तरह ठप रखा, जबकि बतौर पर्यवेक्षण अधिकारी कांके थानेदार ने भी लापरवाही बरती। महीनों बीत जाने के बाद भी न किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई, न ही अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद विभागीय स्तर पर कांड की समीक्षा की गई, जिसमें कई गंभीर त्रुटियां सामने आईं। शेष पेज 03 पर

- महीनों बीत जाने के बाद भी अदालत में दाखिल नहीं की गई चार्जशीट
- अनुसंधान प्रक्रिया पर झारखंड उच्च न्यायालय ने उठाए गंभीर सवाल
- विभागीय स्तर पर मामले की हुई समीक्षा, कई गंभीर त्रुटियां आईं सामने
- किसी भी थाने में लंबित मामलों की निगरानी और नियमित समीक्षा थाना प्रभारी की होती है जिम्मेदारी

सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को दी गई जानकारी
कांके थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू
जिम्मेवर अधिकारियों पर अनमानना की कार्रवाई की चेतावनी
चार सप्ताह में कार्यरत हो जाएगा सूचना आयोग
झारखण्ड उच्च न्यायालय

विभागीय कार्यवाही के बावजूद कांके थाना प्रभारी की चल रही थानेदारी

रांची के एसएसपी राकेश रंजन बोले- पूरे मामले की करेंगे जांच, शिकायत की भी लेगी इंक्वायरी, की जाएगी कार्रवाई
अनुसासनालक प्रक्रिया निपटा, इसकी और बिना इसका के रुपी की जा सके, इसके लिए निर्णियि करने का है नियम
'द फोटोन न्यूज' ने उठाया था मुद्दा खबर की ली सख्त करते हुए 'पत्रा' पर किया गया फेट, उठाए गए कई सवाल
हेविंग कोर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने थानेदार पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने की दी जानकारी
क्या कहती है राज्य की सरकारी सेवक नियमावली
झारखंड सरकारी सेवक (अनुशासन, नियंत्रण और अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(1)(ए) के अनुसार, सक्षम अफसर को यह अधिकार है कि वह किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकता है, यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो या उस पर विचार किया जा रहा हो। यह प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है, ताकि जांच या अनुशासनात्मक प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रभावी और बिना किसी बाधा के आयोजित हो सके और साक्ष्य प्रभावित न हों। इसलिये यह सुनिश्चित होता है कि संबंधित कर्मी अपने पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित न कर सके। नियम के तहत निलंबन का आदेश निर्दिष्ट समय में जारी किया जाना अनिवार्य है। निलंबन को दंड नहीं माना जाता, बल्कि इसे प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित कर्मी अपने पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित न कर सके।

दो-दो विभागीय कार्यवाही चलने पर भी कर रहे थानेदारी, नियमों की हो रही अनदेखी

कांके थानेदार के खिलाफ दो-दो विभागीय कार्यवाही चल रही है, लेकिन अभी भी वे अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होना स्भाविक है। विभागीय कार्रवाई के दौरान प्रकाश रजक को उसी थाने में थानेदार के पद पर बनाए रखते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम 9(1)(ए) के अनुसार, किसी सरकारी अफसर पर अगर अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो या चल रही हो तो उसे निलंबित करने या हटाने का नियम है। ऐसा इसलिए, ताकि किसी भी कारण से जांच प्रभावित न हो। इस मामले में तो निष्पक्ष जांच की अपेक्षा थी पर ऐसा नहीं हो रहा है। देखा जाए तो इस पूरे जांचदल की प्रभावित न होने देने में सीधा इंजार सीनेट, डीजीपी उदासा सिंघा और रांची के एसएसपी राकेश रंजन से शिकायत की गई है। इसमें थानाध्यक्ष जारी रहने के बावजूद कांके थानेदार उसी पद पर आसीन हैं, जिस पद पर रहते हुए उन पर विभागीय कार्यवाही शुरू है। कांके थाना प्रभारी की मनमानी पर भी कार्यवाही के अलावा लगाए गए आरोपों के बीच थानेदार कांके थाना का कमान संभाले हुए हैं। वीरोत्तम है कि झारखंड हाईकोर्ट में दायमेन्त नाम याचिका की ओर से दायर हेविंग कार्पस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कांके थानेदार पर विभागीय कार्यवाही शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। शेष पेज-3 पर पढ़ें

वारंट लेने के लिए आवेदन तक नहीं दिया

कांके थाना में यह मामला 13 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धाराएं 190/126(2)/115(2)/109/117/352/74/61(2) के तहत 15 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में इतनी लापरवाही बरती गई कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वारंट लेने के लिए कोर्ट में आवेदन तक नहीं दिया। आदेश के कहा गया है कि किसी भी थाने में लंबित मामलों की निगरानी और नियमित समीक्षा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होती है। जांच में उत्पन्न तकनीकी या अन्य समस्याओं का समाधान करना और समय से निष्पादन करना पर्यवेक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस स्थिति में कांके थाना प्रभारी की भी बरती गई घोर लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में 4 आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 30 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की गुणवत्ता पर गंभीर टिप्पणी की थी।

SHARE

सेंसेक्स	:	84,065.75
निफ्टी	:	25,867.30

SARAFA

सोना	:	14,710
चांदी	:	300.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

इसरो ने की चंद्रयान-4 लैंडर के लिए लैंडिंग स्थल की पहचान

BENGALURU : इंडियन स्पेस रिसर्च आगेर्नाईजेशन (इसरो) ने चंद्रयान-4 मिशन शुरू होने से कम से कम दो साल पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अपने लैंडर के उतरने के लिए एक स्थल की पहचान कर ली है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के नमूने लाए जाएंगे। यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा मिशन होगा। इसरो के अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने मोंस माउटन (एमएम) क्षेत्र के चार स्थलों का चयन किया और उनमें से एक को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए उपयुक्त पाया। मोंस माउटन चंद्रमा का एक क्षेत्र है। एमएम-1, एमएम-3, एमएम-4 और एमएम-5 स्थानों की पहचान की गई, जिनमें से एमएम-4 को लैंडिंग के लिए चुना गया।

रिक्त पड़े पदों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, राज्य सरकार को दिया निर्देश

लोकायुक्त-मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए तय की जाए समय-सीमा

यदि सरकार संतोषजनक व ठोस जवाब देने में विफल रही, तो कोर्ट छह सप्ताह के भीतर पारित करेगा आदेश

PHOTON NEWS RANCHI :
सोमवार को झारखंड में लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह नियुक्तियों को लेकर ठोस समय-सीमा बताए। चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का मामला फिलहाल उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस विषय में राज्य सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही है। हालांकि, महाधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने अदालत से कुछ समय देने का अनुरोध किया।

- चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई सुनवाई
- कोर्ट में उपस्थित हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन, नियुक्ति संबंधी स्थिति की दी जानकारी
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन

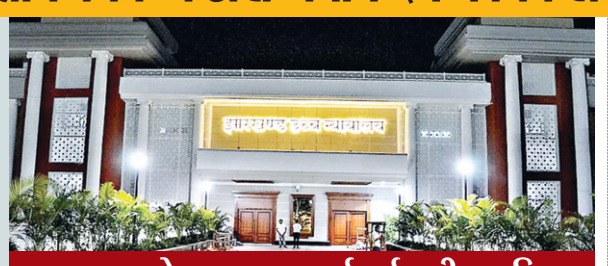

सरकार के रुख पर जताई गई कड़ी आपत्ति

जनहित याचिका की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी सिंह ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीते चार वर्षों से इन महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर केवल समय मांग रही है, लेकिन अब तक न तो लोकायुक्त और न ही मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।

कामकाज हो रहा प्रभावित

संस्थाओं का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है और आम जनता को न्याय एवं संरक्षण से जुड़े मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति आखिर कब तक की जाएगी। अदालत ने कहा कि यदि सरकार संतोषजनक और ठोस जवाब देने में विफल रहती है, तो वह छह सप्ताह के भीतर इन दोनों पदों पर नियुक्ति का आदेश पारित करने पर विचार करेगी।

ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार

सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार रखा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। यह मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/ 2026 से संबंधित है, जिसमें ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल आफ इंडिया एसवी राजू, अधिवक्ता एके दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सीआईएसएफ/बीएसएफ या अन्य अर्धसैनिक बल तैनात करें।

'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण का दूसरा एपिसोड

डरमुक्त भविष्य बनाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी : पीएम

PHOTON NEWS RANCHI :
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण के दूसरे एपिसोड में देश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि आत्मविश्वास और अनुशासन के माध्यम से ही डरमुक्त भविष्य बनता है। विद्यार्थियों को परीक्षा को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। परीक्षा जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सीखने और खुद को समझने का अवसर है। सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और संतुलित जीवनशैली

से छात्र न केवल परीक्षा में सफल हो सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस विशेष एपिसोड में तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, असम के गुवाहाटी और गुजरात के आदिवासी छात्रों से सीधे संवाद किया।

ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ईडी ने सीज की 86.61 करोड़ की चल-अचल संपत्ति

PHOTON NEWS RANCHI :
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के दौरान कथित कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 86.61 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को स्थायी रूप से सीज कर दिया है। इस कुल जब्ती में सबसे बड़ा हिस्सा तत्कालीन मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम और उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्तियों का है, जिसकी राशि 48.94 करोड़ रुपये बताई गई है। ईडी ने इससे पहले इस संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया था। बाद में न्यायाधिकरण ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए जब्ती को स्थायी करने का आदेश दे दिया।

जब्ती में 48.94 करोड़ है सिर्फ मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम के परिवार का हिस्सा

कागजी तौर पर दिखाया गया था कम मूल्य

ईडी की जांच में सामने आया कि बीरेंद्र राम, उनकी पत्नी राज कुमारी और पिता गेंदा राम के नाम पर दिल्ली और अन्य शहरों में महंगी संपत्तियां खरीदी गईं। इन संपत्तियों की खरीद में कागजी मूल्य कम बताया गया, जबकि वास्तविक भुगतान में भारी मात्रा में नकद राशि का उपयोग किया गया। दिल्ली के साकेत में पत्नी राज कुमारी के नाम पर पांच करोड़ रुपये में फ्लैट खरीदा गया, जिसमें 1.78 करोड़ रुपये बैंक के माध्यम से और 3.22 करोड़ रुपये नकद दिए गए। डिफेंस कॉलोनी में 11.30 करोड़ रुपये में एक और फ्लैट खरीदा गया, जिसमें लगभग 6.35 करोड़ रुपये नकद भुगतान बताया गया। नई दिल्ली के साकेत क्षेत्र में गेंदा राम के नाम पर दो बीघा आठ बिसवा जमीन पर 22.50 करोड़ रुपये की लागत से फार्महाउस बनाया गया। इसमें भी बड़ी राशि नकद भुगतान के रूप में दी गई।

झारखंड के सभी प्रमंडलों में डिविजनल कमिश्नर का पद रिक्त, प्रभावित हो रहा काम

NIKHIL KUMAR @ RANCHI :
झारखंड के सभी पांचों प्रमंडलों में प्रमंडलीय आयुक्त (कमिश्नर) का पद वर्तमान में रिक्त है, जिससे प्रमंडलीय स्तर का प्रशासनिक कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। हालांकि कार्यकारी व्यवस्था में डीसी इंचार्ज रहते हैं, लेकिन नियमित कमिश्नर नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। राज्य में पांच प्रमंडल- दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तर छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना और पलामू हैं। लेकिन, इनमें से किसी में भी फिलहाल नियमित आयुक्त पदस्थ नहीं हैं। राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में पदस्थापित रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनके स्थान पर अब तक किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल (रांची) में आयुक्त रहे अंजनी कुमार मिश्र के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हो गया है। वहीं, दो माह से अधिक समय से पलामू प्रमंडल के आयुक्त का पद भी रिक्त चल रहा है। हजारीबाग प्रमंडल में आयुक्त पवन कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक नियमित आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। फिलहाल वहां किसी को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है। इसी तरह कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त नेल्सन इयोन बागे भी 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तीन माह से संथाल परगना प्रमंडल में भी आयुक्त नहीं हैं। आयुक्त का पद खाली रहने से विकास संबंधी योजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक समन्वय, राजस्व के कार्य और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल पर सीधा असर पड़ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार, प्रमंडलीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबित हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

- पहले के आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद नहीं दी गई है किसी को जिम्मेदारी
- कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त नेल्सन इयोन बागे 30 नवंबर 2025 को ही हो चुके सेवानिवृत्त
- राजस्व के कार्य और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल पर सीधे पड़ रहा असर

चिंताजनक स्वास्थ्य व शुद्धता की कसौटी पर खरा नहीं उतरने की हुई पुष्टि

बोतलबंद पानी में मिले जहरीले रसायनों से खड़े हुए कई सवाल

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :
सामान्यतः लोग पीने के पानी के रूप में बोतलबंद पानी को मुख्य रूप से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर या मिनरल वाटर के रूप में जानते हैं। यह प्लास्टिक या कांच की बोतलों में बंद शुद्ध पेयजल माना जाता है, जो उपभोग के लिए सीलबंद होता है। मिनरल वाटर में खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से होते हैं, जो भूमिगत स्रोतों से आते हैं। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर सामान्य पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस (आरवो) या अन्य प्रक्रियाओं से उपचारित करके बोतलों में पैक किया जाता है। दुनिया भर में बोतलबंद पानी की खपत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। लोग इसे सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षित पीने के पानी के विकल्प के तौर पर देखते हैं। बोतलबंद पानी स्वास्थ्य और शुद्धता की गारंटी मानकर खरीदा जाता है, लेकिन हाल में किए गए नए वैज्ञानिक अध्ययन ने इस धारणा पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस विषय पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के रसायन और जैव-रसायन विभाग के वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया है। शोध का उद्देश्य यह जानना था कि बोतलबंद पानी में केवल वे डाइसइंफेक्शन बाय-प्रोडक्ट्स (डीबीपीएस) मौजूद हैं या नहीं, जिन पर नियम लागू हैं या फिर ऐसे प्राथमिक और बिना नियमबद्ध डीबीपीएस भी हैं, जिन्हें अब तक गंभीरता से नहीं परखा गया।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक की स्टडी

नल के जल से 10 पॉपुलर ब्रांडों की तुलना

अनुसंधानकर्ताओं ने दुनिया के 10 लोकप्रिय ब्रांडों का विश्लेषण किया और उनकी तुलना क्लोरामिनयुक्त नल के पानी से की गई। अध्ययन के अनुसार, सभी जांचे गए बोतलबंद पानी ब्रांडों में डीबीपीएस मौजूद थे। इनकी मात्रा 0.01 से 22.4 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के बीच रही, जबकि औसत मात्रा 2.6 माइक्रोग्राम चाहिए। चिंता की बात यह है कि कुछ अत्यधिक विषैले डीबीपीएस भी पाए गए। डिब्रोमोएसीटोनीट्राइल, जिसे कैंसरजनक माना जाता है, दो ब्रांडों में पाया गया।

वाटर रिसर्च पत्रिका में अनुसंधान के नतीजों को विस्तार से किया गया है प्रकाशित

- बड़े ब्रांडों के प्रोडक्ट में भी पाए गए सेहत के लिए हानिकारक रासायनिक तत्व
- रिवर्स ऑस्मोसिस या अन्य प्रक्रियाओं से उपचारित कर बोतलों में किया जाता पैक

सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षित पीने के पानी के विकल्प के तौर पर देखते हैं लोग

पूरी तरह सुरक्षित मान लेना उचित नहीं

वैज्ञानिकों के अनुसार, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीन, क्लोरामाइन, क्लोरीन डाइऑक्साइड या ओजोन जैसे रसायनों से कीटाणुशोधन किया जाता है। यह प्रक्रिया पानी में मौजूद प्राकृतिक ऑर्गेनिक पदार्थों, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया करके अनजाने में नए रासायनिक यौगिक बना देती है। शोधकताओं के अनुसार, बोतलबंद पानी को पूरी तरह सुरक्षित मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन नल के पानी की तुलना में इसमें हानिकारक रसायन कम पाए जाते हैं। बदलती जीवनशैली और बढ़ती खपत के दौर में यह अध्ययन चेतावनी है कि शुद्ध पानी के दावों की वैज्ञानिक जांच और कड़े मानक समय की मांग हैं।

लोस में राहुल को बोलने देने की मांग पर अड़ा विपक्ष कार्यवाही स्थगित

NEW DELHI : सोमवार को संसद के बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग को लेकर कई बार बाधित होने के बाद अंत में अगले दिन पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने आठ सदस्यों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का अवसर न दिए जाने के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। इस दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन में मौजूद रहीं। लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक और फिर 02 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने कांग्रेस सदस्य शशि थरूर को बजट पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन थरूर ने पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अपील की और अपनी सीट पर बैठ गए।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर किया नामांकन, प्रत्याशी पर एफआईआर

गोड्डा के निवर्तमान पार्षद प्रीतम के खिलाफ राजस्व निरीक्षक की शिकायत

PHOTON NEWS GODDA : नगर परिषद चुनाव के बीच फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए वार्ड पार्षद के पद पर नामांकन करने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में निवर्तमान पार्षद प्रीतम गाड़िया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर थाना में उनके खिलाफ धोखाधड़ी की एफआइआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने पूरे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन लेने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया है। वार्ड पार्षद पद के निवार्ची पदाधिकारी सह जिला सामाजिक सुरक्षा निदेशक अभय कुमार झा ने बताया कि नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान गाड़िया के नामांकन पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। इस कारण उनका नामांकन वैध मानते हुए उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया था। बाद में सदर अंचल के राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर उनके खिलाफ गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा। इसके बाद उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब इस मामले में आखिरी फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के निदेर्शों के आधार पर ही लिया जाएगा। फिलहाल आरओ के स्तर से उनकी उम्मीदवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरोपी प्रीतम गाड़िया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती देने की बात कही है। उनका कहना है कि वे नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि वे चुनाव मैदान में पूरी तैयारी डटे रहेंगे।

वार्ड नंबर 6 से लगातार दो बार पार्षद रह चुके हैं प्रीतम

बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर छह से प्रीतम गाड़िया लगातार दो बार पार्षद रह चुके हैं। पहले यह सीट सामान्य श्रेणी की थी, लेकिन इस बार इसे बीसी-टू वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। आरोप है कि अग्रवाल जाति से होने के बावजूद उन्होंने खुद को अग्रहरि वैश्य बताते हुए शपथ पत्र दिया और बीसी-टू का जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया।

गलत खतियानी दस्तावेज देकर बनवाया प्रमाणपत्र

प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने गलत खतियानी दस्तावेज पेश कर आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश की। अंचल अधिकारी के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश मंडल ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इसे धोखाधड़ी का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस से निलंबित होने के बाद फूट-फूट कर रोईं जेबा खान

JAMSHEDPUR : मानगो नगर निगम में मेयर पद की उम्मीदवार जेबा खान उर्फ शाइस्ता परवीन कांग्रेस से निलंबित होने के बाद सोमवार को फूट-फूट कर रोईं। उन्होंने पत्रकारों को अपना दर्द सुनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह पहुंचते ही रोने लगीं। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि उनके निलंबन के पीछे बन्ना गुप्ता का दबाव है। उन्होंने संगठन पर दबाव बनाया। इसी के चलते पार्टी ने यह फैसला किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता रघुवर दास के साथ गलबंहिया करते हुए फोटो भी पत्रकारों को दिखाई और कहा कि बन्ना गुप्ता ने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। जेबा खान ने कहा कि वह कांग्रेस की सच्ची सिपाही रही हैं और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में भी शामिल रही हैं। जेब खान ने कहा कि अब उनका भविष्य जनता के हाथ में है। जनता जो फैसला करेगी वह मानेंगी।

बन्ना गुप्ता पर लगाया संगठन पर दबाव बनाने का आरोप

मेयर पद के लिए नामांकन के बाद बढ़ी रार : गौरतलब है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता को कांग्रेस ने मानगो में मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। जेबा खान ने भी सुधा गुप्ता के सामने अपना नामांकन कर दिया था। जेबा खान भी कांग्रेस की नेत्री थीं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जेबा खान को अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया था लेकिन वह नहीं मानीं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक ने जेबा खान से बात की थी। लेकिन वह जिद पर अड़ी रहीं कि वह कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुधा गुप्ता के खिलाफ हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। जेबा खान का कहना था कि यह मानगो का चुनाव है। इसके बाद कांग्रेस के झारखंड सह प्रभारी बलजीत सिंह बेदी ने रविवार को जेबा खान को कांग्रेस से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था।

साल 2014 में राजनीति में उतरी थी जेबा खान : गौरतलब है कि जेबा खान साल 2014 में राजनीति में तब आई थीं जब जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार जेबा खान के पति फिरोज खान नामांकन के फौरन बाद जेल भेज दिए गए थे। पति के जेल जाने के बाद जेबा खान ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सरयू राय जीते थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे थे। फिरोज खान को सिर्फ 1776 वोट मिले थे।

BRIEF NEWS

प्रेम प्रसंग में छात्र व छात्रा ने फांसी लगा दे दी जान

KODERMA : कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में रविवार को दो नाबालिगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इनमें से एक कक्षा 11 का छात्र और दूसरी कक्षा 10 की छात्रा थी। बताते हैं कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को इसकी जानकारी होने पर दोनों के परिवार के लोगों ने उन्हें डांटा-फटकारा था और पढ़ाई पर फोकस करने की हिदायत दी थी। बताते हैं कि इसी डांट-फटकार के बाद दोनों ने अलग-अलग अपने-अपने घरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और अलग-अलग दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच की जा रही है। घटना डोमचांच थाना क्षेत्र के तेतरियाडीह और बेहराडीह की है। बताते हैं कि तेतरियाडीह का रहने वाला कक्षा 11 का छात्र बड़ाडीह की कक्षा 10 की छात्रा से प्रेम करता था। दोनों के बीच एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच कुछ दिन पहले इसकी भनक परिवार वालों को लग गई। इस पर दोनों के ऊपर बंदिशें लगाई गईं। इसी के चलते आत्महत्या की यह घटना हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों के बयान लिए गए हैं। कुछ विरोधाभासी तथ्य सामने आए हैं। इनको खंगाला जा रहा है।

चतरा डीएसपी व दो थाना प्रभारी हाईकोर्ट में तलब

CHATRA : झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान मैट्रिक के छात्र को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में चतरा के डीएसपी को कोर्ट में सशरीर तलब कर लिया है। डीएसपी के अलावा लावालौंग और टंडवा के थाना प्रभारियों को भी सशरीर कोर्ट में आने का आदेश दिया गया है। इन तीनों को मामले की अगली तारीख 13 फरवरी को हाई कोर्ट में पेश होना है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने मैट्रिक छात्र को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले की सुनवाई की। एसपी इस मामले में ऑनलाइन हाजिर हुए। अदालत ने एसपी से मामले की केस डायरी पढ़कर सुनाने को कहा। केस डायरी में मैट्रिक की छात्रा से 27 और 30 जनवरी को हुई पूछताछ का जिक्र मिला। हाईकोर्ट ने केस के आईओ को भी निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख 13 फरवरी को केस डायरी के साथ कोर्ट में हाजिर हों। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और एके राय की खंडपीठ ने की। चतरा डीएसपी और लावालौंग व टंडवा थाना प्रभारी के मोबाइल पहली पाली की सुनवाई में जब्त कर लिए गए थे। दोनों थाना प्रभारियों को कोर्ट रूम में बैठने का आदेश दिया गया था। बाद में उनके मोबाइल लौटा दिए गए और अगली सुनवाई में उन्हें सशरीर उपस्थित रहने को कहा गया है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि 26 जनवरी की रात 2:00 बजे छात्रों को क्यों उठाया गया और अगर उठाया भी गया तो पूछताछ के बाद तुरंत उन्हें क्यों नहीं छोड़ा गया। 10 दिन तक अवैध रूप से क्यों हिरासत में रखा गया। कोर्ट का कहना था कि जब एक मामले में टंडवा थाना में केस दर्ज है और उसी संबंधित मामले में पूछताछ के लिए छात्रों को उठाया गया है तो क्या केस डायरी में इसका जिक्र किया गया है। इस पर डीएसपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्टेशन डायरी में इस संबंध में लिखा गया है। इसके बाद कोर्ट ने मोबाइल पर चतरा एसपी से बात की और केस डायरी के बारे में जानकारी ली।

मैट्रिक के छात्रों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का मामला

टोटो चलाने के विवाद में ड्राइवर की धारदार हथियार से वार कर हत्या

विरोध में चालकों ने महाराजपुर-तीनपहाड़ रोड को किया जाम, पहुंची पुलिस

कत्ल की वारदात के बाद कल्याणचक बाजार में दहशत, दुकानों के शटर डाउन

PHOTON NEWS RAJMAHAL : राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक बाजार में सोमवार की सुबह टोटो चलाने के विवाद में कुछ लोगों ने धारदार हथियार से वार कर एक ड्राइवर की हत्या कर दी। घटना सोमवार की सुबह 11:00 बजे की है। इस घटना से कल्याणचक बाजार में सनसनी फैल गई और दुकानदारों ने दुकानों के शटर गिरा दिए।

बताते हैं कि मृतक ड्राइवर 28 वर्षीय मंतोष मंडल दलाही फाटक के पास का रहने वाला था। हत्यारोपियों ने जब उस पर हमला किया तो नजदीक में उसका भाई प्रीतम मंडल भी मौजूद था। उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की। घटना में प्रीतम मंडल भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के विरोध में टोटो ड्राइवर ने कल्याण चक बाजार में महाराजपुर तीन पहाड़ मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे आवागमन अवरुद्ध हो गया और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

ड्राइवरों की मांग है कि हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। जाम लगने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम खत्म कराया।

घटनास्थल पर जुटे लोग

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नजदीक में दुर्गा मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर लिए गए हैं। इसमें हत्या की पूरी घटना कैद है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हत्यारोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

घटनास्थल के पास ही है मृतक के भाई की दुकान

वहीं मंतोष मंडल के भाई प्रीतम मंडल की चप्पल की दुकान है। प्रीतम मंडल ने जैसे ही देखा कि कुछ लोग मंतोष मंडल पर हमला कर रहे हैं। वह भाई को बचाने दौड़ा। इस घटना में प्रीतम मंडल को भी चोट आई है। दिनदहाड़े हुई हत्या की इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बाजार के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और सड़क जाम कर दी। पुलिस ने किसी तरह बातचीत कर जाम हटवाया।

सुबह भी हुआ था झगड़ा

बताया जा रहा है कि टोटो चालक मंतोष मंडल का एक अन्य टोटो चालक से कई दिनों से विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तभी राजमहल थाना क्षेत्र के काला बहियार गांव से लोग पहुंचे और इन लोगों ने मंतोष मंडल पर हमला बोल दिया। इस हमले में मंतोष मंडल गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके सर और सीने में धारदार हथियार से वार किए गए थे। जहां पर घटना हुई।

हत्याकांड का पर्दाफाश, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुरानी रंजिश में हुई थी बीरेंद्र कोरवा की हत्या

PHOTON NEWS GARHWA : भंडरिया थाना क्षेत्र के अजगरवा जंगल में गुरुवार को आपसी दुश्मनी को लेकर हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में भंडरिया थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक सुभाष कुमार पासवान ने रोदो गांव से चार आरोपियों को गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह जानकारी पुलिस उपाधीक्षक रोहित रंजन सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय वेश्म में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है।

उन्होंने बताया कि पांच फरवरी को रोदो गांव के बिरेंद्र कोरवा (35 वर्ष) की गला दबा कर हत्या किए जाने के मामले में मृतक के चचेरे भाई कईल कोरवा के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया था। बाद में हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने रोदो गांव के रहने वाले सुरेश भुईयां, अजय भुईयां, राजनाथ भुईयां तथा सीताराम भुईयां को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है । पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि इन चारों आरोपियों ने योजना बना कर पुरानी रंजिश के तहत बीरेंद्र कोरवा की हत्या कर शव को अजगरवा जंगल में छिपा दिया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले पांच फरवरी को मृतक बीरेंद्र कोरवा अपने साइकल से बिराजपुर बाजार गया था। घर लौटते समय वह अकेला था। रास्ते में सुनसान जंगल पाकर अजगरवा जंगल में घात लगाए बैठे लोगों ने झाड़ी में ले जाकर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी थी। शव को छिपाने की नीयत से घटना स्थल से काफी दूर घने जंगल में शव को छिपा कर फरार हो गए थे। घटना के अनुसंधान के क्रम में हत्यारों का पता चला तथा उनकी गिरफ्तारी के बाद घटना में प्रयुक्त होन्डा शाइन मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल और मृतक की साइकिल बरामद की गई है। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस उपाधीक्षक द्वारा गठित टीम में पुलिस निरीक्षक सुभाष कुमार पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक दिलीप कुमार रंजन, किशोर कुमार, संतु सिंह व नन्द कुमार रवि के अलावा आधा दर्जन आरक्षियों थे।

मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

बोकारो के जंगलों में ड्रोन से हो रही हाथियों की निगरानी

BOKARO : फरवरी का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हुआ है। झारखंड से अभी ठंड ने विदाई नहीं ली है। सुबह और रात में ठंड पड़ रही है। ऐसे में झारखंड का एक ऐसा इलाका भी है जहां, हाथियों का उत्पात और उसके भय के कारण लोगों को पड़ोसियों की छतों सोना पड़ रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हाथियों के उत्पात से बचाने और उनका लोकेशन जानने के लिए विभाग की ओर से एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हाथियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके लिए वन विभाग ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से विशेषज्ञों की टीम बुलाई है। प्रत्येक टीम में 5-5 सदस्य रखे गए हैं। ये लोग रात में विभिन्न इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही ड्रोन से इन हाथियों पर नजर रख रहे हैं ताकि उनको आसानी से जंगल में खदेड़ा जाए। बोकारो के गोमिया इलाके में अभी भी हाथियों का उत्पात खत्म नहीं हुआ है। इसके कारण लोगों में काफी भय व्याप्त है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग के प्रति अपनी नाराजगी भी जताई है। उन लोगों ने आरोप लगाया कि इस मामले को सुलझाने के लिए विभाग की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है।

- पश्चिम बंगाल से बुलाई गई है हाथी विशेषज्ञों की टीम
- गजराज के आतंक से लोग दूसरों के घरों में सोने को मजबूर

क्या है घटना

गौरतलब है कि इन दिनों हाथियों का एक झुंड महुआटांड़, बड़की पुन्नु और लुगुबुरु इलाके में उत्पात मचा रहा है, जिसके कारण लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि शाम ढलने के साथ हाथियों का झुंड इन इलाकों में चला आ कर खेतों, मकानों और लोगों पर हमला कर रहा है। यहां बता दें कि, इन दिनों गजराज के हमले से कई लोगों की मौत हो चुकी है।

छत पर रात गुजारने के लिए लोग विवश

स्थानीय लोगों ने बताया कि इन इलाकों में जिनके भी कच्चे मकान हैं, वे अपने पड़ोसियों की छत पर ठंड में रात गुजारने को मजबूर है। जैसे ही शाम होती है हाथियों के डर से घर की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे छत पर चले जाते हैं कि किसी भी तरह उनकी जान बच जाएं।

टी-20 भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के अलावा वीरेंद्र सहवाग व हरभजन सिंह समेत अन्य थामेंगे बल्ला

मैदान में उतरेंगे फिल्मी सितारे व क्रिकेटर, होंगे रोमांचक मुकाबले

PHOTON NEWS LOHARDAGA : लोहरदगा के बलदेव साहू महाविद्यालय क्रिकेट स्टेडियम में 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कई रोमांचक मुकाबले होंगे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है। इस टूर्नामेंट को लेकर लोहरदगा के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। टूर्नामेंट में फिल्मी और क्रिकेट के सितारों के अलावा राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होंगी। इस टूर्नामेंट में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह आ रही हैं।

वह भी मैदान में उतरकर बल्लेबाजी करती नजर आएंगी। अक्षरा सिंह 10 फरवरी को मैच खेलेंगी। इसके अलावा 13 फरवरी को होने वाले मैच में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और स्पिनर हरभजन सिंह मैच खेलने आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई अन्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अलावा जिले के कई राजनीतिक संगठन और जनप्रतिनिधि इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके पुत्र हर्षित साहू आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। टूर्नामेंट को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजक टीम बनाई गई है। बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट के दौरान अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए लोगों को आयोजन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह दो अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे और पांच-पांच ओवर का प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। टूर्नामेंट में स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी खेल सकते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई है।

बताया जा रहा है कि इस टूर्नामेंट को लेकर लोहरदगा ही नहीं आसपास के जिलों में प्रचार-प्रसार चल रहा है। स्टेडियम में लोगों के बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम रहेंगे। पुलिस के अलावा, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाउंसर का भी इंतजाम रहेगा।

इसी स्टेडियम में टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन

ओबीसी विचार मंच ने की सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर में भारतीय ओबीसी विचार मंच ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। भारतीय ओबीसी विचार मंच की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन झारखंड के राज्यपाल के माध्यम से भेजा गया है। ज्ञापन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। संगठन का कहना है कि करीब 31 साल पुराने मामले में जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है, वह न्यायसंगत नहीं है। मंच ने उन्हें लगातार छह बार निर्वाचित सांसद बताते हुए कहा है कि पप्पू यादव अपने क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं और हमेशा जनता के हित में खड़े रहे हैं। भारतीय ओबीसी विचार मंच ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि पूरे मामले में उचित न्याय करते हुए पप्पू यादव को अविलंब रिहा किया जाए, ताकि वे अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

फैमिली प्लानिंग में पुरुष पीछे, महिलाओं के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी

2025 में मात्र 44 पुरुषों ने नसबंदी कराने में दिखाया इंटरेस्ट, 2845 महिलाओं ने कराया ऑपरेशन

- इस काम को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहा स्वास्थ्य विभाग
- समाज में फैलीं भ्रांतियां व जागरूकता की कमी के कारण भी पुरुषों में अधिक संकोच

पुरुषों को भी आना होगा आगे

पिछले वर्षों के आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि कैसे पुरुष महिलाओं से पीछे हैं। 2022-23 में 216 पुरुष नसबंदी के मुकाबले 4,803 महिला नसबंदी के मामले सामने आए थे। वहीं 2023-24 में पुरुष नसबंदी के मामलों में हल्की वृद्धि होकर संख्या 269 तक पहुंची, लेकिन महिला नसबंदी के मामले बढ़कर 5,317 हो गए। सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि मामूली बढ़ोतरी के बावजूद परिवार नियोजन की स्थायी जिम्मेदारी का बोझ अब भी मुख्य रूप से महिलाओं पर ही है। चूंकि परिवार भी दबाव अपने घर के पुरुषों की बजाय महिलाओं पर ही बनाता है।

सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि

पुरुष भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है। वासेक्टॉमी करवाने वाले पुरुषों को 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि महिला नसबंदी पर 2000 रुपये मिलते हैं। प्रसव के सात दिनों के भीतर नसबंदी कराने वाली महिलाओं को 3000 रुपये तक की राशि मिलती है। इसके बावजूद पुरुष नसबंदी को लेकर प्रतिक्रिया बेहद सीमित बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता अभियान, मिथकों को दूर करने और सामाजिक सोच में बदलाव के जरिए ही पुरुषों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। जिससे फैमिली प्लानिंग में संतुलित जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।

VIVEK SHARMA, RANCHI : परिवार को संभालने के साथ महिलाएं अब पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। घर हो, ऑफिस हो, मार्केटिंग कहीं भी वे पुरुषों से पीछे नहीं है। लेकिन, बात फैमिली प्लानिंग की हो तो पुरुष उनसे काफी पीछे है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल मात्र 44 पुरुषों ने नसबंदी करने में इंटरेस्ट दिखाया, जबकि इस दौरान 2,845 महिलाओं ने नसबंदी कराई। इससे साफ है कि आज भी फैमिली प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। पुरुष अब भी फैमिली प्लानिंग के लिए महिलाओं को ही आगे बढ़ा दे रहे हैं। बता दें कि फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग करोड़ों रुपये भी खर्च कर रहा है। वहीं उत्प्रेरक को भी सम्मान राशि दी जा रही है। इसके बावजूद पुरुष इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि पुरुष नसबंदी को लेकर समाज में फैली भ्रांतियां, जागरूकता की कमी और सामाजिक कलंक इसकी कम पार्टिसिपेशन के प्रमुख कारण हैं। कई पुरुष अब भी यह मानते हैं कि वासेक्टॉमी से शारीरिक क्षमता या लाइफस्टाइल प्रभावित होती है, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह एक सुरक्षित, सरल और कम समय में होने वाली प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति जल्द सामान्य जीवन में लौट सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी की तुलना में कहीं अधिक आसान और कम जटिल प्रक्रिया है। जिसमें केवल मामूली सर्जरी की जरूरत होती है। इसके बावजूद सामाजिक मिथक और झिझक पुरुषों को इस विकल्प को अपनाने से रोक रहे हैं।

डीडीसी की ओर से दी गईं सुविधाओं को वापस करने की उठने लगी आवाज

कई जिलों में मनरेगा लोकपाल को नहीं मिला अवधि विस्तार

पलामू व रामगढ़ के डीडीसी ने 8 फरवरी को कार्यकाल खत्म होने की दी जानकारी

- शिकायत निवारण व निगरानी का काम प्रभावित होने की जताई जा रही आशंका
- मंतव्य मांगने पर ग्रामीण विकास विभाग से नहीं मिला अवधि विस्तार का आदेश

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत लगभग कई जिलों में नियुक्त लोकपाल को अवधि विस्तार नहीं दिया गया। लोकपाल को अवधि विस्तार नहीं दिए जाने से अब उन्हें विभिन्न जिलों के उपविकास आयुक्त (डीडीसी) द्वारा दी गई सुविधाओं को वापस करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में पलामू और रामगढ़ के डीडीसी ने वहां के लोकपाल को पत्र भी लिखा है। जारी पत्र के अनुसार, संबंधित लोकपाल का कार्यकाल 8 फरवरी को समाप्त हो गया है। बताया गया है कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें आगे सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। इससे मनरेगा में शिकायत निवारण और निगरानी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस विषय में ग्रामीण विकास विभाग से पूर्व में इस पर मंतव्य मांगा गया था, पर वहां से अवधि विस्तार का कोई आदेश नहीं दिया गया। ऐसे में मनरेगा से जुड़ी अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया ठप पड़ सकती है। अधिकारियों के अनुसार, इनकी जगह नई नियुक्ति की जाएगी।

बेहद अहम मानी जाती है लोकपाल की भूमिका

मनरेगा लोकपाल की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। लोकपाल का मुख्य कार्य मनरेगा योजना में गड़बड़ी, फर्जी जॉब कार्ड, मजदूरी भुगतान में अनियमितता, कार्य स्थल पर सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच करना होता है। लोकपाल को स्वतंत्र रूप से जांच करने, संबंधित पदाधिकारियों से जवाब तलब करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का अधिकार होता है।

प्रतीकात्मक फोटो

सिफारिशों के आधार पर होती है कार्रवाई

मनरेगा में लोकपाल की सिफारिशों के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई भी की जाती है। लोकपाल को अवधि विस्तार नहीं मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में देरी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि लोकपाल की अनुपस्थिति में मजदूरों की शिकायतें लंबित रहेंगी और योजना की पारदर्शिता पर भी असर पड़ेगा।

हजारीबाग के पूर्व डीएसओ पर चलेगी विभागीय कार्यवाही

RANCHI : राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी व तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी हजारीबाग अरविंद कुमार पर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है। इनके खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभागीय ने 2023 में ही कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने यह फैसला लिया है। विभागीय जांच का संचालन रिटायर आईएएस अधिकारी सुनील कुमार को सौंपा गया है। अरविंद कुमार को 15 दिनों के अंदर अपना लिखित बचाव बयान सौंपने का निर्देश दिया गया है। उनके खिलाफ मुख्य रूप से पांच

आरोप लगाए हैं, जिनमें झारखंड जनवितरण प्रणाली के नियमों का अनुपालन नहीं करने, मनमाने तरीके से डीलरों को निलंबित करने एवं 10 दिनों के अंदर की अवैध वसूली कर निलंबन मुक्त करने तथा गोदाम प्रबंधकों एवं डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्ता से अवैध वसूली करने, पैक्स के जरिए महज 14 किसानों का भुगतान, राइस मिल की सही टैगिंग नहीं करनी है। कार्मिक विभाग ने जांच से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी गयासुद्दीन अहमद ने दिया निर्देश

मरीजों के ट्रीटमेंट पैकेज री-एडमिशन और एआई से निगरानी पर करना है फोकस

- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लेकर की गई समीक्षा

प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैकेज का रिव्यू

प्राइवेट हॉस्पिटलों में बीमारियों के हिसाब से पैकेज उपयोग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ विशिष्ट बीमारियों में दावों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। बैठक में 30 दिनों के भीतर मरीजों के री-एडमिशन से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही ऐसे हॉस्पिटलों और पैकेज की पहचान की गई, जहां री-एडमिशन की दर अधिक है। इस पर उपचार की गुणवत्ता, फॉलो-अप व्यवस्था और मानक उपचार प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन पर जोर दिया गया। टीएमएस और स्टेट डेटा वेयरहाउस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी की जा रही है।

PHOTON NEWS RANCHI : सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी गयासुद्दीन अहमद ने झारखंड सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा की। इस दौरान झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष छवि रंजन, महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शी सुनील प्रसाद सिंह, विश्वजीत प्रसाद और वैभव राय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान गयासुद्दीन अहमद ने केंद्र और राज्य के बीच समन्वय, आईटी सिस्टम को मजबूत करने और निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति, वित्तीय स्थिति, तकनीकी व्यवस्था और निगरानी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने बताया कि झारखंड में 66 लाख परिवार आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से कवर है। वहीं 2.80 करोड़ लाभुक है। जिन्हें निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल सूचीबद्ध हैं। जहां पैकेज के माध्यम से गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है।

BRIEF NEWS

रांची में आज 619 बूथों पर खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा

RANCHI : फाइलेरिया (हाथीपांव) के उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 10 फरवरी को जिले के 619 बूथों पर स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा फाइलेरिया रोधी दवाएं लोगों को खिलाई जाएगी। सिविल सर्जन रांची डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम जिले के प्रभावित प्रखंडों राहे, तमाड़, सोनाहातु और कांके में संचालित होगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 4 लाख 91 हजार 14 लोगों को दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि, गर्भवती महिलाएं, दो वर्ष से कम आयु के बच्चे और अत्यंत गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये दवा नहीं दी जाएगी। लोगों को डीईसी और एल्बेंडाजोल दवा पूरी तरह निःशुल्क और सुरक्षित रूप से दी जाएगी।

पीपल्सकेयर हॉस्पिटल का मनाया गया चौथा स्थापना दिवस

RANCHI : सोमवार को रातू रिंग रोड स्थित तिलता चौक के समीप स्थित पीपल्सकेयर हॉस्पिटल ने अपने सेवा के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्थापना दिवस मनाया। मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और आम नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संचालक जेपी पांडेय एवं श्वेता पांडेय ने इस मौके पर कहा कि हॉस्पिटल की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को किफायती, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बीते चार वर्षों में हॉस्पिटल ने निरंतर सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए लोगों का विश्वास जीता है। उन्होंने डॉक्टरों, कर्मचारियों और मरीजों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ही यह उपलब्धि संभव हो सकी है। इस अवसर पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने भविष्य में और अधिक आधुनिक सुविधाएं जोड़ने तथा सेवा क्षेत्र का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई।

तुपुदाना में दुकान से नकद व मोबाइलों की चोरी

RANCHI : रांची के तुपुदाना थाना क्षेत्र स्थित गुटनू मोबाइल दुकान में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान संचालक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि रात लगभग दो बजे चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और नकद राशि सहित कई स्मार्ट मोबाइल फोन व एक्सेसरीज चोरी कर ली। चोरी गए सामान में गल्ले से लगभग ₹27,000 नकद और कई महंगे स्मार्टफोन शामिल हैं। संचालक ने तुपुदाना थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर घटना की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है।

झारखंड के लिए गौरव और प्रेरणा के प्रतीक हैं वीर बुधु भगत : शिल्पी

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वीर बुधु भगत हमारे मांडर क्षेत्र के गौरव और प्रेरणा के प्रतीक हैं। उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मंत्री शिल्पी नेता तिर्की ने सोमवार को यह बात चाह्लो के सिलागाई में वीर बुधु भगत स्मारक समिति के पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक में बोलते हुए कही। बैठक में आगामी 17 फरवरी को वीर बुधु भगत की 234वीं जयंती समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि समारोह में हर साल की तरह इस बार भी भव्यता बरकरार

रहे। समारोह के दिन आयोजित विकास मेला में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में जयंती समारोह के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया और आसपास के गांवों और प्रखंडों तक कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और योजना के योग्य लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

राजधानी को गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने तेज किया अभियान

PHOTON NEWS RANCHI : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने शहर को गार्बेज फ्री सिटी बनाने का अभियान तेज कर दिया है। जिससे कि रांची को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। नगर निगम योजनाबद्ध तरीके से शहर के सभी वार्डों में नियमित सफाई कार्य करा रहा है। हर दिन सड़कों और मुख्य मार्गों पर झाड़ू लगाने का कार्य किया जा रहा है। आवासीय क्षेत्रों, पार्कों और उद्यानों में प्रतिदिन एक बार, जबकि व्यावसायिक क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, पर्यटन स्थलों और धार्मिक-ऐतिहासिक स्थानों पर प्रतिदिन दो बार सफाई कराई जा रही है।

विजिबल क्लीनलीनेस पर फोकस

सफाई की निगरानी स्वच्छता समन्वयक और स्वच्छता अधीक्षक द्वारा की जा रही है। निरीक्षण के दौरान कहीं भी गंदगी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, ताकि विजिबल क्लीनलीनेस के लक्ष्य को प्रभावी रूप से हासिल किया जा सके। इसी क्रम में सोमवार को मेन रोड, अपर बाजार, हरमू बाईपास रोड, मोरहाबादी, सर्कुलर रोड, कडरू, धुर्वा, हिनू, डोरंडा, बरियातू रोड, बूटी मोड़ और कोकर सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर सफाई मित्रों द्वारा व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। रांची नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाएं और शहर को स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। सफाई से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18005701235 पर संपर्क किया जा सकता है।

NEWS BOX

निकाय चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग में की शिकायत

PHOTON NEWS RANCHI : राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव ने किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद राज्य सरकार के इशारे पर मंइयां योजनाह्ल से जुड़ी खबरें राज्य के सभी प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित करवाई गईं। इन खबरों में योजना की लाभुक महिलाओं को बिना गारंटी 20 हजार रुपये तक का लोन दिए जाने की जानकारी दी गई है। यह पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, लेकिन राज्य सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मंइयां योजना को चुनाव से जोड़कर महिला मतदाताओं को प्रलोभन देने का प्रयास कर रही है, जो निष्पक्ष चुनाव की भावना के विरुद्ध है।

सफाईकर्मी के शव के साथ लोगों ने दिया धरना

PHOTON NEWS KANKE : सीआइपी में कार्यकरत सफाईकर्मी बिरसा कच्छप के शव के साथ ग्रामीणों ने संस्थान के मुख्य द्वार पर धरना दिया।

ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य का सीआईपी में सरकारी नौकरी, घटना की न्यायिक जांच, दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगे थी। धरना का समर्थन कांके विधायक सुरेश बैठा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम, कांग्रेस नेता जमील अख्तर, निशा भगत, जेएलकेएम के फुलेश्वर बैठा व देवेंद्र महतो, जिप सदस्य किरण देवी, प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव सहित अन्य ने प्रदर्शनकारियों ग्रामीण का समर्थन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे सीआईपी परिसर में कांके पुलिस बल व अतरिक्त सुरक्षा बल तैनात थी। इस मामले में मृतक के भाई प्रदीप कच्छप ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांके थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

विरोध

2024 की वैकेंसी में संशोधन और आयु सीमा में विशेष छूट की उठाई आवाज

जेपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

PHOTON NEWS RANCHI : जेपीएससी आफिस के बाहर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2024 की वैकेंसी में संशोधन और आयु सीमा में विशेष छूट दी जानी चाहिए। साथ ही कहा कि वर्तमान नियमों के कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार प्रतियोगिता प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, जो न केवल अनुचित है बल्कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय भी है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को रखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीते कई वर्षों से विभिन्न प्रशासनिक और अन्य कारणों से प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं। परीक्षा में हुई इस देरी के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जबकि वे पूरी तरह योग्य हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने 2024 की वैकेंसी में आयु सीमा में विशेष छूट देने की मांग की है, ताकि सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि जेपीएससी ने समय-समय पर भर्ती नियमों और शर्तों में बदलाव किए। लेकिन अभ्यर्थियों के हित में कोई ठोस और स्थायी निर्णय नहीं लिया गया। इस वजह से ही अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज मांगों को आयोग और राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।

आंदोलन की चेतावनी

सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम

इससे पहले अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर जेपीएससी आफिस के बाहर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात थे। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे।

रांची से बच्ची लापता, पता बताने वाले को पुलिस देगी 21 हजार का इनाम

RANCHI : डोरंडा थाना क्षेत्र से एक 12 वर्षीय बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है।

लापता बच्ची का नाम नेहा टोप्पो बताया गया है, जो 4 फरवरी 2026 को डोरंडा थाना क्षेत्र के गिरजाटोली डिबडीह से अचानक गायब हो गई। इस घटना के बाद परिजन चिंतित है। इसे लेकर डोरंडा थाना पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है। जिसमें पता बताने वाले को 21 हजार इनाम देने की घोषणा की गई है। नेहा टोप्पो के पिता का नाम सीताराम टोप्पो है। स्थायी पता ग्राम जटहरी डीह, पोस्ट मरयाचक (महागामा) थाना हनवारा, जिला गोड्डा है। वर्तमान में वह अपने परिवार के साथ रांची जिले के डोरंडा थाना क्षेत्र में रह रही थी।

पेज एक का शेष

कांके थानेदार कर रहे लापरवाही...

हाईकोर्ट के सहायक लोक अभियोजक साकेत कुमार के पत्र के माध्यम से यह तथ्य सामने आया कि जमानत खारिज होने के 9 माह बीत गए, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए रांची एसएसपी को प्रतिवेदन दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद एसएसपी ने रांची के सभी थानेदार, इंस्पेक्टर और ओपी प्रभारियों को भी सख्त आदेश दिया है। एसएसपी ने आदेश में कहा है कि थानेदार खुद या आईओ के जरिए कोर्ट के रिकॉर्ड का समय से जांच कर इस तरह के मामलों को चिह्नित कर काईवाई करें। लापरवाही बरतने पर केस के आईओ और थानेदार के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसएसपी ने सभी डीएसपी को आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। एसएसपी ने सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी को भी लंबति मामलों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

समाचार सार

बास्केटबॉल लीग में टीम मैडनेस बनी चैंपियन

SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां जिला बास्केटबॉल संघ द्वारा, झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में गोविंद विद्यालय, तामुलिया में आश्मिता बास्केटबॉल लीग 2025-26 (खेलो इंडिया) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस लीग में कुल 8 प्रतिस्पर्धी टीमों ने भाग लिया। इससे पूरा टूनार्मेंट बेहद रोमांचक बन गया। कार्यक्रम में कई अतिथियों की उपस्थिति रही। इनमें गोविंद विद्यालय के सचिव अभिषेक शर्मा, मानगो नगर निगम के ब्रांड एंबेसडर मुख्तार आलम खान, गोविंद विद्यालय की एचओडी प्रमुख एन रज़िया, झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव एवं भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच जेपी सिंह, एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी, टेक्निकल हेड आरिफ आफताब, कार्यकारिणी सदस्य जलाल शेख, निजाम अली और सुप्रिया करन शामिल हैं।

टूनार्मेंट के परिणाम : तृतीय स्थानः आइएसडब्लूपी टीम, **द्वितीय स्थानः** टाटा स्टील ट्रेनिंग टीम, **प्रथम स्थान/चैंपियनः** टीम मैडनेस, **सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ीः** रीता अग्रवाल (टीम मैडनेस)। विजेता टीमों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को विशेष रूप से नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जिन अधिकारियों और सदस्यों का विशेष योगदान रहा, उनमें शाबानुल हक, अजहर खान, अमित शर्मा, अंजलि, राहुल सोना, हरीश, विशाल दास, दीपक साहू और अरहान शामिल रहे।

डायवर्सन तोड़ खेत में घुसा तेज रफ्तार ट्रक

GHATSILA : बहरागोड़ा प्रखंड के भूतिया पंचायत के चंद्रपुर गांव में रविवार देर रात करीब 2 बजे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तेज रफ्तार एक ट्रक (डब्ल्यूबी 33 के 0419) अनियंत्रित होकर पुलिया के डायवर्सन को तोड़ते हुए खेत में घुस गया। हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोट लगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले, तब देखा कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में है। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई राहगीर या ग्रामीण मौजूद नहीं था, अन्यथा जान-माल का काफी नुकसान हो सकता था। बताया जा रहा है कि ट्रक चाकुलिया की ओर जा रही था। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से होकर रात के समय लगातार भारी वाहनों का आवागमन होता रहता है, जो माटीहाना होते हुए चाकुलिया के रास्ते पश्चिम बंगाल की ओर जाता है। भूतिया पंचायत के मुखिया विधान चंद्र मंडी ने आरोप लगाया कि हर रात बड़ी संख्या में ट्रक आयरन मिट्टी लोड कर दुगार्पुर की ओर जाते हैं। यह ट्रक चेक नाका से बचने के लिए इसी ग्रामीण मार्ग का उपयोग करते हैं।

जमात के साथ विदेश गए 6 युवक एनआईए के राडार पर

JAMSHEDPUR : कपाली के छह युवक जमात के साथ विदेश गए थे। उनके लौटने के बाद एनआइए इन युवकों की जांच कर रही है। आशंका है कि यह लोग आतंकियों के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एनआइए ने धतकीडीह के रहने वाले अब्दुल सामी और रज्जाक कॉलोनी के नसीम से भी पूछताछ की है। अब्दुल सामी 18 जनवरी साल 2016 को हरियाणा के मेवात से और नसीम जमशेदपुर से गिरफ्तार हुआ था। बाद में कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था।

मैट्रिक में 40 व इंटर की परीक्षा में 4 रहे अनुपस्थित

GHATSILA : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के छठे दिन सोमवार को घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में परीक्षा कदाचारमुक्त रही। सोमवार को दोनों स्तरों की परीक्षा सभी केंद्रों पर आयोजित की गई। मैट्रिक परीक्षा में कुल 7342 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 7302 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 40 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 1095 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 1091 उपस्थित हुए तथा 4 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

केयू में कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल का गठन

JAMSHEDPUR : कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में शैक्षणिक एवं संस्थागत विकास को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल (सीडीसी) का गठन कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस परिषद का उद्देश्य विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्रभावी बनाना है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय की कुलपति परिषद की अध्यक्ष होंगी। वहीं प्रो-कुलपति, वित्तीय सलाहकार, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, प्रॉक्टर, कुलसचिव एवं विकास पदाधिकारी पदेन सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किए गए हैं। विज्ञान संकाय से डॉ. निरीश कुमार महतो, डॉ. सोमनाथ कर एवं डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता को सदस्य नामित किया गया है। कला संकाय से डॉ. टी. के. खांडा एवं डॉ. रमेंद्र रजक तथा वाणिज्य संकाय से डॉ. भवानी मुंडी को परिषद में स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध घाटशिला कॉलेज, टाटा कॉलेज, जे.आर. को-ऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, बहरागोड़ा कॉलेज एवं महिला महाविद्यालय सरायकेला-खरसावां के प्राचार्यों को भी परिषद का सदस्य बनाया गया है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को हुई 25 साल की सजा

कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत दो युवकों को 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार अदालत ने एक नाबालिग के साथ जबरदस्ती दो युवकों ने दुष्कर्म किया था। इसी मामले में सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मामले में सुनवाई के दौरान दोषी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के महुलसाई के रहने वाले सुनील देवगन और झींकपानी के रवि टुटुगुटू गांव के रवि उर्फ गोमिया पुरती को सजा सुनाई गई। चाईबासा मुफ्फसिल थाना में 24 मई 2022 को सुनील देवगन और रवि उर्फ गोमिया पुरती के खिलाफ एक नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया था कि आरोपी

अभियुक्त सुनील देवगन और रवि उर्फ गोमिया पुरती के द्वारा पीड़ित नाबालिग का अपहरण कर उसका बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने नाबालिग को धमकी दी थी कि अगर इस बात को किसी को बताया तो उसकी हत्या कर देंगे और साथ ही परिजनों की भी हत्या कर देंगे। पीड़िता ने अपने परिजन को पूरी घटना बताई थी। इसके बात परिवार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चाईबासा मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज कराया था। पोक्सो एक्ट के आरोपी सुनील देवगन और रवि उर्फ गोमिया पुरती को सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने 25 साल की सजा सुनाई और दोनों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

सजायाफ्ता दोषी

चाईबासा में दोस्त की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में चक्रधरपुर के युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई है। यह हत्या साल 2020 में चाईबासा के सराईकेला मोड़ के पास हुई थी। हत्या की इस घटना को दोषी जावेद ने पत्थर से कुचलकर अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार मुफ्फसिल थाना में 19 जुलाई 2020 को हत्या का यह केस दर्ज किया था। घटना को अंजाम देने वाला जावेद चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पोटका का रहने वाला है। उसकी चक्रधरपुर के लोकनाथ नगर के राजु मुखी से दोस्ती थी। लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई थी। इसलिए जावेद ने 18 जुलाई 2020 राजू मुखी को धोखा दे कर चाईबासा बुला ले गया। इसके बाद आरोपी ने मौका देखकर सराईकेला मोड़ के पास शमशान घाट जाने वाले रास्ते में शाम 5 बजे पत्थर से कुचलकर राजू मुखी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के लिए उसका चेहरा भी पत्थर से कुचल दिया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। बाद में परिजनों ने कपड़े से युवक की पहचान की थी। चक्रधरपुर में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

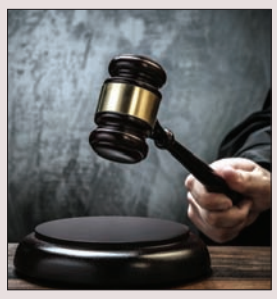

जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था पर सवाल

गायब रहे डॉक्टर, मरीजों को हुई दिक्कत

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला स्वास्थ विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आया है, इस बार जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है। यहां पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त के आदेश के धज्जियां उड़ाते हुए पिछले दो दिनों से डॉक्टर गायब हैं, मरीज परेशान हैं। जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुर के शिव मंदिर टोला निवासी श्याम करुवा का दस वर्षीय पुत्र सम्राट करुवा सोमवार की सुबह छत पर पतंग उड़ाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन उसे जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। काफी देर तक घायल अस्पताल में ही पड़ा रहा, लेकिन जब डॉक्टर नहीं आया। तब परिजनों उसे निजी गाड़ी कर के 18 किलोमीटर दूर टाटा स्टील के नोवामुंडी अस्पताल लेकर पहुंचे। इसी तरह, बीच कोचड़ा गांव की एक सहिया मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गई। उसे भी इलाज के लिए जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टर के अभाव में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। लेकिन, रेफर करने के लिए चिकित्सक नहीं होने के कारण वह अस्पताल में ही तड़पती रही। इधर, घायल बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर नहीं होने पर हो हल्ला किया। इसके बाद, इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र छोटन को दी। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर अंचल अधिकारी मनोज मिश्रा ने जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आकर मामले का जायजा लिया। उन्होंने देखा की मौके पर कोई भी डाक्टर नहीं थे। सभी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी जयंत कुमार को फोन करने पर उन्होंने बताया कि वह 5 दिन की छुट्टी लेकर गए हैं। वहीं, डा बृजमोहन हेस्सा का ट्रांसफर मझगांव हो गया है। एक डेंटल डॉक्टर प्रतिभा कुमारी सप्ताह में तीन दिन आती हैं। आयुष डॉक्टर इकबाल फील्ड पर निकले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जगन्नाथपुर के इतने बड़े अस्पताल में एक भी डॉक्टर का ना होना बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर चिकित्सा प्रभारी छुट्टी में थे, तो सिविल सर्जन के द्वारा क्या दूसरे डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अगर की गई थी तो एक भी डॉक्टर अस्पताल में क्यों नहीं थे। अगर प्रति नियुक्ति नहीं की गई थी तो इसका जिम्मेदार कौन है ,अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या ठोस कदम उठाती है।

जगन्नाथपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

भट्ठियां ध्वस्त कर बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब बरामद

JAMSHEDPUR : मानगो और जुगसलाई नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत, उत्पाद विभाग ने बिरसा नगर में बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर यह विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी सिलसिले में बिरसानगर थाना क्षेत्र के हुरलुंग इलाके में टीम ने दबिश दी। छापेमारी के दौरान अवैध चुलाई शराब बनाने वाली भट्ठियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अवैध शराब बिक्री स्थल से तकरीबन 40 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में जावा महुआ भी नष्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 6000 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया गया, ताकि दोबारा शराब निर्माण न हो सके। उत्पाद विभाग ने साफ किया है कि अवैध शराब कारोबार में शामिल भट्ठी संचालकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर जिले में आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। ऐसा अधिकारियों का कहना है। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इलाके में लगातार रेड कर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाएं।

जावा-महुआ नष्ट करते पुलिस के जवान

तेज रफ्तार बाइक स्कॉर्पियो से टकराई, तीन लोग घायल

अस्पताल में इलाजरत घायल ● फोटोन न्यूज

JADUGORA : जादूगोड़ा में जादूगोड़ा मुख्य मार्ग पर सोमवार को एक सड़क हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में एक युवक और दो युवतियां हैं। बताते हैं कि एक ही बाइक पर सवार होकर गालूडीह की रहने वाली लखी मार्डी, पार्वती मुर्मू और मुसाबनी का रहने वाला युवक कुंडू मार्डी नरवा पहाड़ की तरफ जा रहे थे। उनकी बाइक का काफी तेज रफ्तार में थी। जादूगोड़ा मुख्य मार्ग पर बाइक पीछे से स्कॉर्पियो से टकरा गई। इस सड़क हादसे में लकी मार्डी, पार्वती मुर्मू और कुंडू मार्डी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर जादूगोड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार मंडल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यहां सभी का इलाज चल रहा है। जादूगोड़ा पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बताते हैं कि स्कॉर्पियो सड़क किनारे ही थी, तभी बाइक उससे जा टकराई।

छुट्टे पैसे के विवाद में शंकर स्टोर पर हमला

JAMSHEDPUR : बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर-4 स्थित शंकर स्टोर में मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, कुछ अज्ञात युवकों और दुकानदार के बीच छुट्टे पैसे को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दुकान में घुसकर संचालक और उनके भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। शोर-शराबा सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची उनकी मां को भी धक्का-मुक्की में चोट लग गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने बिरसानगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इलाके में इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश और दहशत का माहौल है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन

आयोजन समिति से कार्यक्रम की जानकारी लेते डीसी व एसएसपी

JAMSHEDPUR : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 फरवरी को जमशेदपुर आ रही हैं। वह यहां कदमा के मरीन ड्राइव पर प्रस्तावित महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी। वह मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आ रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को डीसी कर्ण सत्यार्थी और एसएसपी पीयूष पांडे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां आयोजन समिति के सदस्य भी मौजूद थे। डीसी ने आयोजन समिति के सदस्यों से पूरे कार्यक्रम का ब्योरा जाना और साथ में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि राज्य सरकार ने टाटा स्टील से टाटा लीज की जमीन लेकर संस्था को मंदिर निर्माण के लिए दी है। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हाल ही में जमशेदपुर में राष्ट्रपति का यह दूसरा दौरा है। इसके पहले वह 29 दिसंबर को जमशेदपुर आई थीं।

सड़क पर गिरी स्कूटी को बाइक ने मारी टक्कर, एक की मौत

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना चाईबासा-रांची मुख्य मार्ग पर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के महुलसाई के पास हुई। बताते हैं कि क्रिस्टा हेंब्रम नामक युवक अपनी स्कूटी से तेज रफ्तार में जा रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर पड़ा। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। तभी पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार रोहित दास सड़क पर गिरी स्कूटी और युवक को देख नहीं पाया और सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान टुंगरी निवासी मोटरसाइकिल सवार रोहित दास की मौत हो गई। जबकि, स्कूटी सवार क्रिस्टा हेंब्रम की हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कैरव अपहरण कांड | लोकल इनपुट लेकर लुधियाना के गैंगस्टर ने रची थी किडनैपिंग की साजिश

मास्टरमाइंड का जमशेदपुर लिंक खंगाल रही पुलिस

- आखिर किसने दी थी लुधियाना के गैंगस्टर को लौहनगरी के कारोबारियों की जानकारी

PHOTON NEWS JSR : बिष्टुपुर के सीएच एरिया के मशहूर कारोबारी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी अपहरण केस में अब पुलिस लोकल लिंक की तलाश में जुट गई है। पुलिस को पता चला है कि लुधियाना के गैंगस्टर तेजिंदर पाल सिंह ने जमशेदपुर के कुछ लोकल बदमाशों से इनपुट लेकर घटना को अंजाम दिया था।

पुलिस अब तेजिंदर पाल सिंह का जमशेदपुर लिंक खंगाल रही है। उसकी तलाश की जा रही है जिसने लुधियाना के इस बदमाश को कैरव के बारे में बताया था। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि लुधियाना के तेजिंदर पाल सिंह ने बिहार के बदमाशों के सहारे इस घटना को अंजाम दिया था। बिहार के नालंदा के गुड्डू सिंह व इमरान रेकी करने जमशेदपुर आए थे। मगर, सवाल इस बात का है कि जमशेदपुर में तेजिंदर पाल सिंह की मदद कौन कर रहा था। गुड्डू सिंह और इमरान जब जमशेदपुर आए तो इन्हें किसने रेकी करने में सहायता की। तेजिंदर पाल सिंह को कौन इंटेलीजेंस उपलब्ध करा रहा था।

किसने तेजिंदर पाल सिंह को बताया कि कैरव का अपहरण किया जाए तो फिरौती मिलेगी। इन सबका एक ही जवाब है कि जमशेदपुर में कोई लोकल गिरोह तेजिंदर के संपर्क में था और वहीं उसे सूचना दे रहा था। पुलिस इस लोकल लिंक का पता लगाने में जुटी हुई है।

बताया जा रहा है कि पुलिस सोनारी, कदमा, मानगो, कपाली, गोलमुरी और बागबेड़ा के बदमाशों की टोह ले रही है ताकि, इस घटना का लोकल लिंक तलाश किया जा सके। इसके लिए मुखबिरों का जाल फैला दिया गया है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को बिष्टुपुर के सीएच एरिया के रहने वाले कैरव गांधी का अपहरण कदमा-सोनारी लिंक रोड से कर लिया गया था। पुलिस कैरव गांधी की तलाश में जुटी थी। छापेमारी चल रही थी। इसी बीच 26 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ता कैरव को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने वाले हैं। इस पर पुलिस की टीमें हजारीबाग के पास जीटी रोड के आसपास तैनात थीं। अपहरणकताओं ने कैरव को बरही-चौपारण खंड के पास छोड़ दिया था। पुलिस ने कैरव को बरामद कर उनके घर पहुंचाया था। इसके बाद ताबड़तोड़ दबिश देकर पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं।

फाइल फोटो

घाटशिला कॉलेज में 24 व 25 मार्च को राष्ट्रीय सेमिनार

GHATSILA : घाटशिला कॉलेज में बहुविषयी दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन को लेकर सोमवार को प्राचार्य डॉ आर के चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन को लेकर विविध एजेंसियों से आए प्रस्ताव एवं विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभी दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करवाया जाए। इसके लिए 24 एवं 25 मार्च की तिथि निर्धारित की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह राष्ट्रीय सेमिनार गौतम बुद्ध नैतिक शिक्षा मिशन, झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में करवाया जाए। सेमिनार का विषय भारत @ 2047: शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का भविष्य निर्धारित किया गया। बैठक में इस सेमिनार के आयोजन व्यवस्था को लेकर तत्काल प्राचार्य डॉ आर के चौधरी की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति गठित की गई, इसमें डॉ एसपी सिंह को सदस्य सचिव बनाया गया। बैठक में डॉ डीसी राम, प्रो इंदल पासवान, डॉ संदीप चंद्र, डॉ मोहम्मद सज्जाद, डॉ कुमार विशाल, प्रो राम विनय श्याम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

डराने वाला कभी भी नहीं हो सकता जन नेता : मधु कोड़ा

कार्यक्रम में बोलते पूर्व सीएम मधु कोड़ा ● फोटोन न्यूज

CHAKRADHARPUR : जनता को डरा-चमका कर वोट मांगने वाला कभी जन नेता नहीं हो सकता है। यह बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहीं। वे सोमवार को चक्रधरपुर के रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित सालुजा कॉम्प्लेक्स में नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी डॉ.विजय सिंह गागराई के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसी का नाम लिये बगैर कहा कि कुछ के द्वारा लोगों को यह कहकर डराया जा रहा है, नगर परिषद चुनाव में अगर वोट नहीं मिला तो ठेकेदारी व दुकानदारी बंद कर दूंगा। लोगों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों से बचकर रहना है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि अगर कोई भी डरा धमकाकर वोट करने को कहता है, तो इसकी जानकारी अवश्य दें, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा।

विधानसभा : भाजपा विधायक ने विदेशी नागरिकों का उठाया मुद्दा

AGENCY PATNA : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पांचवें दिन सोमवार को गोपालगंज जिले के बैकठपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिथलेश तिवारी ने प्रश्नकाल के दौरान गृह विभाग से जुड़ा देश की सुरक्षा का गंभीर मामला सदन में उठाया।

विधायक मिथलेश तिवारी ने गोपालगंज जिले में वर्ष 1990 से 2015 के बीच पाकिस्तानी नागरिकों के आगमन और उनके बसने को लेकर सवाल किया। इस पर उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन को आश्वस्त किया कि बिहार में धार्मिक वीजा पर आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की गहन छानबीन की जाएगी। उनके ठहरने, आवागमन और यात्रा से जुड़ी सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। विधायक तिवारी ने सरकार से पूछा कि धार्मिक यात्रा पर आने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया क्या है। उन्होंने कहा कि कई लोग धार्मिक यात्रा के नाम पर भारत आते हैं और बाद में नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग कई क्षेत्रों में आलीशान मकान बना लेते हैं, जमीन-जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और यहां तक कि मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। उन्होंने सदन में कहा कि उनके क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थल थावे मंदिर है, इसके अतिरिक्त कोई बड़ा धार्मिक केंद्र नहीं है, इसके बावजूद वहां विदेशी नागरिकों की लगातार उपस्थिति देखी जाती है। विधायक ने सवाल उठाया कि जब विदेशी नागरिक भारत आते हैं, तो स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन प्रशासन के पास उनके आगमन का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं होता। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इन विदेशी नागरिकों की तस्वीरें ली जाती हैं, क्या इमीग्रेशन विभाग से उनका सत्यापन होता है और क्या उनके आवागमन से संबंधित दस्तावेज विभाग के पास सुरक्षित रहते हैं।

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जांच का दिलाया भरोसा

विधान परिषद में राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा

बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 5वें दिन विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच टकराव देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार ने लॉ-एंड-ऑर्डर को लेकर हंगामा किया। सुनील सिंह ने दरभंगा में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मुद्दा उठाया। इसके बाद विधानपरिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा- 'बिहार का कोई जिला नहीं बचा है, जहां बच्चियां सेफ हों।' सदन में 'नीतीश कुमार हाय-हाय' के नारे लगे। जिसके बाद नीतीश कुमार अपनी सीट से उठे और कहा- 'तुमलोगों ने कुछ काम किया था, जो आज बोल रहे हो। कभी बच्चियों को स्कूल भेजा

था।' विधान परिषद में राजद एमएलसी ने इसके बाद बेल में आकर नारेबाजी की। पटना, खगड़िया आरा, दरभंगा रेप का मामला उठाया। विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, जिसके बाद कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। नीट छात्रा की मौत और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पोर्टिको में नारेबाजी हुई। विपक्ष के विधायकों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। जिसमें लिखा- 'रेप, हत्या, किडनैपिंग कब रुकेगी। कानून है, पर डर नहीं। जवाब दो सरकार।' चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन सांसद की गिरफ्तारी के खिलाफ 'आज जेल होई, कल बेल होई, परसो से वो ही खेल होई' लिखी टी-शर्ट पहनकर पहुंचे। उन्होंने कहा, 'हम पप्पू यादव के साथ खड़े हैं।' वहीं कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा, 'बिहार में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है।'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा-

परिवारवादी दलों से उज्ज्वल नहीं हो सकता देश व बिहार का भविष्य

AGENCY PATNA : बिहार की राजधानी पटना स्थित बापू सभागार में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो पार्टियां स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म हो जाती हैं, उनसे न तो बिहार का और न ही देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

नितिन नवीन ने कहा कि व्यक्तिवादी और परिवारवादी दलों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वे सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती हैं, जबकि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा में संगठन और विचारधारा सर्वोपरि है, न कि व्यक्ति या परिवार।

अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने बिहार में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरूआत की थी और आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बाद भी वे खुद को कार्यकर्ता ही मानते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में पिता के निधन के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उसी समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का आशीर्वाद और पूरे संगठन का समर्थन उन्हें मिला।

नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसे और आगे ले जाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला पटना दौरा है और बिहारवासियों ने उन्हें लगातार विधानसभा सदस्य चुनकर जो स्नेह दिया है, उसके लिए वे आभारी हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक युवा मोर्चा में काम किया है और हमेशा युवाओं को यही संदेश दिया है कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता। राजनीति एक लंबी दौड़ है और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए सभी को अपने-अपने समय में पूरी निष्ठा और पुरुषार्थ के साथ काम करना होगा।

उन्होंने भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की परिकल्पना सामने रखी और अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन का मंत्र दिया। आज भाजपा की सरकारें इन्हीं तीनों महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर देश की सेवा कर रही हैं।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। 45 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पूरे बिहार के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने बताया कि अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान नितिन नवीन कई संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पूर्व बापू सभागार में भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगवा गमछा लहराकर उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से 'जोड़ी मोदी-नीतीश के...' गीत बजाकर उत्साहपूर्ण माहौल बनाया गया।

अभिनंदन समारोह के बाद नितिन नवीन ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। वे 10 फरवरी को बिहार विधानसभा जाएंगे, जहां विधायक और विधानपार्षद उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे के अंतिम दिन 10 फरवरी की शाम वे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा- बिहार में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी और आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बाद भी वे खुद को मानते हैं पार्टी का एक कार्यकर्ता

उत्तर बिहार में कोहरे से विजिबिलिटी शून्य के करीब, रोड पर रेंग रहे वाहन

AGENCY PATNA : उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में सोमवार सुबह प्रकृति का दोहरा वार देखने को मिला। एक तरफ जहां न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं घने कोहरे की सफेद चादर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा,सीतामढ़ी सहित अधिकतर जिले कोहरे की आगोश में है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आज मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। दरभंगा की बात करे तो यहां का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी तरह उत्तर

बिहार के अधिकतर जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पछुआ हवाओं ने वातावरण में कनकनी बढ़ा दी है। ठंडी हवा और नमी के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह टहलने निकलने वाले लोग और कामगार ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते देखे गए।

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में टली सुनवाई

AGENCY PATNA : बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट समेत पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया।

सुरक्षा कारणों से कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिसके चलते पप्पू यादव की बेल पर सुनवाई टल गई और फिलहाल उन्हें बेऊर जेल में ही रहना होगा। सोमवार सुबह पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स और आईईडी से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। इसके बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। एमपी-एमएलए कोर्ट को भी एहतियातन

खाली कराया गया। जगह-जगह तलाशी अभियान चला और कोर्ट की नियमित कार्यवाही प्रभावित हुई। इसी वजह से पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई संभव नहीं हो पाई।

उल्लेखनीय है कि पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी ऐसे समय हुई, जब वे नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन पर हमलावर थे। इस मुद्दे पर उन्होंने कई बार सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से सवाल उठाए थे।

BRIEF NEWS

न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी पूर्णतः झूठी : एसएसपी

BHAGALPUR : एसएसपी कार्यालय के हवाले से सोमवार को बताया गया कि न्यायालय परिसर में बम विस्फोट से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुआ था। उक्त सूचना के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निदेर्शानुसार तत्काल सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से सक्रिय किया गया। निर्देश के क्रम में बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वायड) एवं अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा न्यायालय परिसर की सघन, विस्तृत एवं पूर्ण जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु, विस्फोटक सामग्री अथवा अन्य आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई। जांचोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि प्राप्त सूचना पूर्णतः झूठी एवं भ्रामक थी। वर्तमान में न्यायालय परिसर पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्लियरेंस दिए जाने के पश्चात न्यायालय की नियमित न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही पुनः आरंभ कर दी गई है।

विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए राजस्व कर्मचारी

NAVADA : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघ के आहवान पर नवादा सदर सहित विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिस कारण राजस्व कार्यालय में ताला लटका हुआ है। अपार समाहर्ता ने बताया कि सरकार से मांगों को लेकर राजस्व अधिकारी हड़ताल पर है। कब हड़ताल खत्म होगी। इसमें मेरे स्तर से कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में सरकार का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। कौआकोल प्रखण्ड के सभी राजस्व कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिससे विभागीय राजस्व सम्बन्धित कार्य ठप हो गया है।

एएनएम व जीएनएम छात्रावास में चला जागरूकता अभियान

SARAN : पुलिस अब जिले की बेटियों के सुरक्षा के प्रति न केवल जागरूक कर रही है बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भर रही है। सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर महिला थाना और भगवान बाजार थाना स्थित महिला हेल्प डेस्क द्वारा एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सदर अस्पताल परिसर स्थित छात्रावास में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान महिला थानाध्यक्ष एवं पुलिस टीम ने छात्राओं को महिला सुरक्षा के विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में डायल-112 सेवा का उपयोग कैसे करें। साथ ही उन्हें साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों से आगाह करते हुए सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके भी समझाए गए।

NEWS BOX

ट्रेड डील से भागलपुरी सिल्क से जुड़े बुनकरों में उत्साह

AGENCY BHAGALPUR : ट्रंप सरकार द्वारा 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने के फैसले पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम

ट्रेड डील को लेकर टेक्सटाइल और आर्टिजन उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बिहार के भागलपुर में बुनकर से एक्सपोर्टर बने जियाउर्रहमान ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का सकारात्मक परिणाम है। जियाउर्रहमान के अनुसार अमेरिकी बाजार में भागलपुरी टेक्सटाइल की खास पहचान है और वहां के ग्राहकों को बारीक कारीगरी और हुनर चाहिए जो भागलपुर के कारीगरों के हाथों से तैयार होता है। उनका दावा है कि ऐसी गुणवत्ता और पारंपरिक कला दुनिया के किसी अन्य हिस्से में संभव नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि टैरिफ हटने और ट्रेड डील के प्रभाव से भागलपुर के सिल्क उद्योग को नई मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय बुनकरों, कारीगरों और निर्यात कारोबार से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अपराध-भ्रष्टाचार चरम पर, चुनावी वादे साबित हुए खोखले : पीके

AGENCY PATNA : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार नवनिर्माण यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने

आम जनता से सीधा संवाद किया और बिहार की मौजूदा राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से बड़े-बड़े लोकलुभावन वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बने अभी महज दो महीने ही हुए हैं और राज्य में अपराध तथा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब गंभीरता से यह समझने की जरूरत है कि जिन वादों के आधार पर उनसे वोट मांगा गया था, वे कितने खोखले और झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है। कानून-व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज आंदोलन का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि बिहार नवनिर्माण यात्रा के माध्यम से वे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता के बीच सच्चाई रखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि बिहार को एक नई दिशा दी जा सके।

छपरा व्यवहार न्यायालय में दलीलों की जगह वकीलों के गूंज रहे नारे

AGENCY SARAN : छपरा व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा नियमों को लेकर उपजा विवाद अब एक गंभीर संवैधानिक और प्रशासनिक गतिरोध में बदल

चुका है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा लागू की गई नई सुरक्षा गाइडलाइन के विरोध में जिले के तमाम अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। सोमवार को स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सशस्त्र जवानों और रैपिड एक्शन बलों की तैनाती कर दी गई। अधिवक्ताओं ने इसे अपनी गरिमा पर सीधा प्रहार बताते हुए जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामले की शुरूआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश संख्या 385G/25 और संशोधित आदेश 16G/26 से हुई। इसके तहत कोर्ट के गेट नंबर 1 पर पुलिस बैरियर लगाए गए हैं और नियम बनाया गया है कि सुबह 11:00 बजे के बाद कोई भी वाहन दोपहिया या चार पहिया परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही, प्रवेश के लिए स्कैनर गेट से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि चेकिंग की आड़ में उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सारण बार एसोसिएशन के महामंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह ने दो टूक कहा, अधिवक्ता सुरक्षा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आत्मसम्मान की बलि देकर थोपी गई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि वकालत के पेशे में आवाजाही का कोई निश्चित समय नहीं होता।

गुणवत्ता पीआरडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर ने बताया-

आईएसओ प्रमाणीकरण से ई-गवर्नेंस तक विभाग की बड़ी उपलब्धि

AGENCY PATNA : सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि आईएसओ प्रमाणीकरण से लेकर ई-गवर्नेंस तक सामान्य प्रशासन विभाग बड़ी उपलब्धियां हासिल की है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते डॉ. बी राजेंदर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार तथा बिपार्ड को आईएसओ 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन विभाग को 21 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया, जो विभागीय कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं मानकीकरण का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत राज्य के 14 विभागों की 153 प्रकार की सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, नए राशन कार्ड का निर्माण, मजदूर दुर्घटना अनुदान, चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन, कन्या उत्थान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। अब तक राज्य में 51.13 करोड़ से अधिक आवेदनों का सफल निष्पादन किया जा चुका है।

डॉ बी राजेन्दर ने कहा कि जुलाई 2025 से पंचायत सरकार भवनों/पंचायत भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे नागरिकों को अब प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 45 विभागों की 514 सेवाओं एवं योजनाओं में समयबद्ध एवं पारदर्शी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया गया है। 22 जनवरी 2016 से अब तक 18.57 लाख से अधिक शिकायतों एवं परिवादों का निपटारा किया जा चुका है।

बक्सर में ज्वेलरी दुकान से 20 लाख के जेवरात ले उड़े चोर

BUXAR : धनसोई बाजार में रविवार देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बिहार ग्रामीण बैंक के पास स्थित मां मुंडेश्वरी ज्वेलर्स को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान के पीछे की दीवार के सहारे कटरे में घुसे और शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अलमीरा के ताले को धारदार हथियार से काटकर करीब 20 लाख रुपये मूल्य के आभूषण चुरा लिए। चोरी गए सामान में लगभग चार किलो चांदी और करीब 100 ग्राम सोने के जेवरात शामिल बताए जा रहे हैं। दुकान मालिक सुनील सेठ के पुत्र बिट्टू वर्मा रोज की तरह रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे।

आठ करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से बनेगा बिहपुर थाना भवन : विधायक

AGENCY BHAGALPUR : अष्टादश बिहार विधानसभा के द्वितीय सत्र में बिहपुर विस के भाजपा विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक ई.शैलेंद्र के द्वारा बिहपुर थाना भवन सह पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के बदहाल और जर्जर हो चुके भवन का मुद्दा उठाया था। इस पर सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा के संयुक्त सचिव कमल नयन की ओर से सात फरवरी को विधायक ई.शैलेंद्र को आए जवाब में बताया गया कि बिहपुर थाना भवन (जी प्लस थ्री स्ट्रक्चर) फर्नीचर और अन्य आधारभूत संरचना सहित भवन निर्माण कार्य के लिए आठ करोड़ 57 लाख 75 हजार 300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में दी गई है। उक्त थाना भवन का

निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक ई.शैलेंद्र के हवाले से नवगछिया भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो.गौतम ने बताया कि बिहपुर थाना परिसर में उक्त निर्माण को लेकर प्राथमिक कवायद शुरू भी हो चुकी है। मिट्टी जांच के लिए ले जाया गया है। वहीं परिसर में आम-लीची के पेड़ को लेकर उचित कार्रवाई के लिए वन विभाग को पत्र भी लिखा गया है।

भूल से भी न करें कोई गलती सारा समाज हमारा अपना

हमारा देश इसीलिए महान है, क्योंकि यहां भिन्न-भिन्न विचारधाराएं हैं। लेकिन, जब बात राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की आती है तो समूचा समाज एकजुट होता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का ये संदेश देखिए- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों मे जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए है, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का का फैसला उचित है, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता, अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अन्तर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। वास्तव में ये भावना ही हमारे भारतीय समाज को एक करती है। मायावती वो नेता हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति में आईं। एक समय तक उनके कटु, तीक्ष्ण बयान भी सुने गए। लेकिन, वो अपने तरह की राजनीति है। समाज ने उसे भी स्वीकारा। वो सत्ता के शीर्ष पर भी रहीं, किंतु दूसरी ओर अनुच्छेद 370 के हटाने से लेकर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, ऑपरेशन सिंदूर और अब यूजीसी विवाद - इन सबमें में राष्ट्रीयता के स्वर को मुखरता से रखा है, क्योंकि वो जानती हैं कि देश प्रथम की भावना के साथ ही समाज चल सकता है। राजनीति अपनी जगह है। सत्ता अपनी जगह है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ होती है राष्ट्रीय एकता। मायावती जी ने उसी भाव और प्रतिबद्धता को बारंबार समाज के बीच प्रकट किया है। यही हमारे देश की सुंदरता है। वहीं, सर्वोच्च नियामक संस्था सुप्रीम कोर्ट बारंबार ये बताता है कि संविधान निमार्ताओं की दृष्टि का पालन हर किसी को करना पड़ेगा। उन लोगों से बारंबार निवेदन है जो सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी गाइडलाइन को लेकर दिए गए निर्णय को अपने-अपने चश्मे से देख रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन का 'जातीय चश्मे' से समर्थन और विरोध करने वालों से निवेदन है कि कृपया इसे अहं का विषय न बनाएं। ये न तो किसी जाति या वर्ग की जीत है और न किसी की हार। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सत्यमेव जयते के ध्येय वाक्य पर आधारित है। ये समूचा समाज हमारा अपना है। किसी के साथ कोई भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति, दल या नेता- आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के नाम पर विद्वेष और विभाजन फैलाए, उन्हें पहली फुर्सत में हमें और आपको ही नकारना होगा। आप और हम ये समझें कि जहां भी सामाजिक विभाजन की बात आएगी। अलगाव की बात आएगी। हम सब हर उस व्यक्ति और विचार के खिलाफ खड़े होंगे। जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध इसीलिए है क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये गाइडलाइन सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली और वर्ग के आधार पर विभाजन फैलाने वाली थी।? सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी की नई गाइडलाइन पर अभी लगाए गए स्टे और टिप्पणी ने ये बताया है कि कोई भी नियम, कानून, दिशा-निर्देश सामाजिक एकता, सुरक्षा और भेदभाव दूर करने के लिए लाए जाते हैं, न कि विभाजन फैलाने के लिए। अशांति और उपद्रव के फैलाने के लिए। जाति या वर्ग के नाम पर जो लोग उन्माद फैला रहे हैं। एक-दूसरे को अगर जाने-अनजाने किसी भी रुप में आहत कर रहे हैं तो कृपया ये न करें। क्योंकि अगर हम अपनी जातीय पहचान और जातीय दंभ के नाम पर समाज को बांटेंगे तो ये देश को और समाज को बांटने वाला होगा। सही का साथ, गलत का विरोध करना ही चाहिए। दूषित राजनीति, स्वार्थी तत्व और भारत विरोधी गैंग तैयार बैठ है कि कब हम और आप कोई चूक करें। फिर वो देश में अशांति और वैमनस्य फैलाने में जुट जाएं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद से एक गैंग सक्रिय हो गया है। टूलकिट शुरू हो गई है कि जातीय आधार पर लोगों की भावनाओं को हवा दी जाए। किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाने की पुरजोर कोशिशें जारी हो गई हैं। लच्छेदार शब्दों, इमोशनल ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने का अभियान भी बड़ी चतुराई से शुरू हो चुका है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि विभाजन की चिंगारी से समाज को झुलसने के लिए छोड़ दिया जाए। अतएव सावधानी और सतर्कता रखिए। ये समय शब्दों और बौद्धिक युद्ध का है। देश और समाज के शत्रु घात लगाए बैठे हैं कि कब आपको उद्वेलित किया जाए। कब जातिगत आधार पर समाज को निशाना बनाया जाए। एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया में कंटेट भी खूब सकुर्लेट किए जा रहे हैं। हम सबकी जो शाश्वत पहचान भारतीय होने की है। हिंदू होने की है। उसे कमतर दिखाने और जातीय पहचान को बड़ा दिखाने का अभियान भी शातिर बदमाश शुरू कर चुके हैं। युवाओं से विशेष निवेदन है कि धैर्य के साथ काम करें। आपका समर्थन और विरोध अपनी जगह हो सकता है। आक्रोश और उत्साह अपनी जगह है। लेकिन, हम कहीं भी कोई ऐसी बात न कहें, न लिखें, न किसी की ऐसी बात सुनें जो किसी भी प्रकार के विभाजन को हवा देने वाली हो, क्योंकि स्वार्थी राजनीति, विभाजन फैलाने वाले लोग हमें आपस में लड़ा देंगे। इसमें उनके स्वार्थ होंगे।

रुपये की गिरावट को इतना हल्के में मत लीजिए

ANALYSIS

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लगभग 35 प्रतिशत का यह अवमूल्यन विदेशी मुद्रा बाजार का आंकड़ा आज भारत की एक हकीकत है, जो साफ तौर पर कहता है कि ये स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था की गहरी और संरचनात्मक कमजोरियों का दर्पण है। अब इस सच्चाई को न तो वैश्विक परिस्थितियों के बहाने ढंका जा सकता है और न ही मजबूत बुनियादी कारकों के दावों से खारिज किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने रुपये की गिरावट को उभरते बाजारों की मुद्राओं की सामूहिक कमजोरी का हिस्सा बताया। बेशक इसमें आंशिक सच्चाई है, वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास बना हुआ है और अमेरिका की सख्त मौद्रिक नीति ने डॉलर को मजबूत किया है, किंतु सवाल यह है कि जब वैश्विक दबाव लगभग सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर समान है, तब भारत का रुपया अपेक्षाकृत अधिक दबाव में क्यों है। यहीं से घरेलू आर्थिक चूकों की ओर ध्यान जाता है और इनकी जांच अनिवार्य हो जाती है। पिछले डेढ़ वर्षों में भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति कमजोर हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 40 अरब डॉलर घटकर लगभग 650 अरब डॉलर रह गया।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल में संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को सरकार एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। यह समझौता निःस्संदेह भारत के निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा करता है और दीर्घकाल में व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने की क्षमता रखता है, किंतु इसी उत्सवधर्मी माहौल के बीच एक गंभीर आर्थिक संकेत डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का निरंतर कमजोर होने को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। देखा जाए तो वर्ष 2013 में जहां एक डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 68 के स्तर पर था, वहीं जनवरी 2026 तक यह 92 (91.95 रुपये प्रति डॉलर) के करीब पहुंच चुका। लगभग 35 प्रतिशत का यह अवमूल्यन विदेशी मुद्रा बाजार का आंकड़ा आज भारत की एक हकीकत है, जो साफ तौर पर कहता है कि ये स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था की गहरी और संरचनात्मक कमजोरियों का दर्पण है। अब इस सच्चाई को न तो वैश्विक परिस्थितियों के बहाने ढंका जा सकता है और न ही मजबूत बुनियादी कारकों के दावों से खारिज किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने रुपये की गिरावट को उभरते बाजारों की मुद्राओं की सामूहिक कमजोरी का हिस्सा बताया। बेशक इसमें आंशिक सच्चाई है, वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास बना हुआ है और अमेरिका की सख्त मौद्रिक नीति ने डॉलर को मजबूत किया है, किंतु सवाल यह है कि जब वैश्विक दबाव लगभग सभी

उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर समान है, तब भारत का रुपया अपेक्षाकृत अधिक दबाव में क्यों है। यहीं से घरेलू आर्थिक चूकों की ओर ध्यान जाता है और इनकी जांच अनिवार्य हो जाती है। पिछले डेढ़ वर्षों में भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति कमजोर हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 40 अरब डॉलर घटकर लगभग 650 अरब डॉलर रह गया। इसी दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी तेज रही। अकेले जनवरी 2026 में लगभग 5 अरब डॉलर का पूंजी बहिर्गमन दर्ज किया गया, जिसका सीधा असर रुपये पर पड़ा। हालांकि यह भी सच है कि 16 जनवरी तक विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 अरब डॉलर के स्तर को छू गया था, जिससे भारत लगभग 11 महीनों के आयात को कवर कर सकता है। यह भंडार देश के कुल बकाया विदेशी कर्ज के करीब 94 प्रतिशत के बराबर है और वैश्विक झटकों से निपटने के लिए एक मजबूत लिक्विडिटी बफर प्रदान करता है। पर साथ में यही भंडार भारत की आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था की कमजोर नस को भी उजागर करता है। क्योंकि ये विदेशी मुद्रा जिस तेजी से आती हुई दिखती है, उतनी ही तेजी से अचानक निकासी करती हुई भी दिखी है। यानी कि इस पर भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही यह भी एक तथ्य है कि वर्ष 2025 में भारत ने लगभग 800 टन सोने का आयात किया, जिस पर 60 अरब डॉलर से अधिक खर्च हुआ। कोयला, कच्चा तेल और उर्वरकों का आयात बिल भी लगातार बढ़ता गया। परिणामस्वरूप चालू खाते का घाटा (सीएडी) जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिसे किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत माना जाता है। सरकार निर्यात वृद्धि को रुपये की मजबूती का आधार बताती रही है। इसमें संदेह नहीं कि सेवा क्षेत्र का निर्यात प्रभावशाली रहा है। 2005 से 2024 के बीच भारत का सेवा निर्यात ढाई गुना बढ़ा और वैश्विक सेवाओं के निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 4.3 प्रतिशत तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जिसमें सेवाओं का योगदान 387.6 अरब डॉलर था। दूरसंचार उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और ऑटोमोबाइल्स के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। लेकिन, इसके बावजूद वस्तु व्यापार में भारत भारी घाटे में बना हुआ है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट आज भी लगभग 200 अरब डॉलर के आसपास है। यही असंतुलन रुपये पर लगातार दबाव बनाए रखता है और सेवा निर्यात की सफलता इस सच्चाई को छिपा नहीं पाती। अब बात भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए की गहराई से करते हैं, जिसके तहत 97 प्रतिशत भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में प्राथमिकता मिलेगी और 70 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर शून्य सीमा शुल्क लागू होगा। कपड़ा, चमड़ा, मसाले, गहने, समुद्री उत्पाद और श्रम-साध्य उद्योगों के लिए इसे एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से यह समझौता रुपये को मजबूती दे सकता है, किंतु वर्तमान हकीकत यह है कि यूरोपीय संघ के बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी आज भी लगभग दो प्रतिशत के आसपास अटकी हुई है। इसका मुख्य कारण भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की सीमित क्षमता और गुणवत्ता मानकों में कमजोरी है। जब तक यह समझौता पूरी तरह जमीनी स्तर पर प्रभावी होगा, तब तक रुपये के सामने नए संकट खड़े हो सकते हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जीडीपी में लगभग 17 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 28 प्रतिशत और वियतनाम में लगभग 25 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि बिना मजबूत विनिर्माण आधार के एफटीए जैसे समझौते भी रुपये को स्थायी मजबूती नहीं दे सकते। हालांकि भारत ने डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए हैं। रूस के साथ रुपये-रूबल में तेल व्यापार इसका उदाहरण है, लेकिन यह प्रयोग 10 अरब डॉलर के स्तर से आगे नहीं बढ़ सका। समस्या यह रही कि रूस के पास जमा हुए रुपयों के उपयोग का व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल पाया। आज भी भारत का लगभग 80 प्रतिशत विदेशी व्यापार डॉलर आधारित है और पेट्रोलियम व्यापार का 90 प्रतिशत हिस्सा डॉलर में होता है। तीव्र प्रणाली और अमेरिकी बॉन्ड बाजार डॉलर की बादशाहत को और मजबूत करते हैं। ऐसे में सवाल यह नहीं कि डॉलर को चुनौती देना कितना कठिन है, बल्कि यह है कि जब ब्राजील या इंडोनेशिया अपनी मुद्रा को अपेक्षाकृत स्थिर रख सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कहना होगा कि इसका उत्तर उत्पादकता, निर्यात संरचना और आयात निर्भरता में छिपा है। रुपये की कमजोरी का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। आयात महंगा होने से पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और उर्वरकों की कीमतें बढ़ती हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुकी हैं। उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और अंततः इसका भार करदाताओं पर पड़ता है। साथ ही छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए डॉलर में लिया गया कर्ज महंगा हो जाता है। ऐसे में यहां समझने वाली बात यह है कि किसी भी मुद्रा की मजबूती चालू खाते के संतुलन, उच्च उत्पादकता, विविधीकृत निर्यात और नियंत्रित आयात निर्भरता पर निर्भर करती है। भारत इन सभी मोर्चों पर अब भी अधूरा दिखता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के कहे अनुसार रुपये की कमजोरी को सिर्फ वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम मान लेना आत्मसंतोष होगा।

भारत का निम्न मध्यम आय से उच्च आय श्रेणी में अग्रसर होना

भारत आज अपने आर्थिक इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस गति से परिवर्तन और विस्तार देखने को मिला है, उसने न केवल देश के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भारत के निम्न मध्यम आय श्रेणी से उच्च मध्यम आय श्रेणी में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को निम्न आय श्रेणी से बाहर निकलकर निम्न मध्यम आय श्रेणी में पहुंचने में लगभग 60 वर्षों का समय लगा। वर्ष 1962 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मात्र 90 अमेरिकी डॉलर थी, जो मिश्रित वार्षिक 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2007 में बढ़कर 910 अमेरिकी डॉलर हो गई। इसी वर्ष भारत को विश्व बैंक द्वारा औपचारिक रूप से निम्न मध्यम आय श्रेणी में शामिल किया गया। यह परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव था, किंतु इसके पश्चात विकास की गति में जो तेजी आई, वह कहीं अधिक उल्लेखनीय सिद्ध हुई। यदि सकल घरेलू उत्पाद के आकार पर दृष्टि डालें, तो भारत को वर्ष 2007 में एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग छह दशक लगे। इसके पश्चात मात्र सात वर्षों में, अर्थात वर्ष 2014 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर दो लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। इसके अगले सात वर्षों में वर्ष 2021 तक यह तीन लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल चार वर्षों के भीतर वर्ष 2025 में भारत ने चार लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का आंकड़ा भी पार कर लिया। विभिन्न आर्थिक आकलनों के अनुसार आगामी दो से तीन वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद पांच लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को भी पार कर सकता है। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भी भारत की प्रगति इसी प्रवृत्ति को दशार्ती है। वर्ष 2009 में भारत को प्रति व्यक्ति आय के 1000 अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचने में 62 वर्षों का समय लगा था, किंतु इसके बाद केवल दस वर्षों अर्थात वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2000 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गई। वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय 3000 अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 4000 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर सकती है। इसी आधार पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2030 तक भारत निम्न मध्यम आय श्रेणी से निकल कर उच्च मध्यम आय श्रेणी में प्रवेश कर जाएगा, जिस श्रेणी में आज चीन और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। विश्व बैंक द्वारा विश्व के देशों को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय शामिल हैं। वर्तमान परिभाषा के अनुसार किसी देश को उच्च आय श्रेणी में शामिल होने के लिए उसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 13,926 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करनी आवश्यक होती है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 7.5 प्रतिशत की वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर बनाए रखनी होगी। यह वृद्धि दर अव्यावहारिक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पिछले 23 वर्षों के दौरान भारत की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रही है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारत आगामी कुछ वर्षों में ही प्रति व्यक्ति औसत आय 4500 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करते हुए उच्च मध्यम आय श्रेणी में शामिल हो सकता है। इसके पश्चात वर्ष 2047 तक उच्च आय श्रेणी में प्रवेश करने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति आय को लगभग 18 हजार अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँचाना होगा। इसके लिए आगामी 23 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 8.9 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनाती हैं, जिनका लाभ समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्ग तक सुनिश्चित रूप से पहुँचे तो यह लक्ष्य भी कठिन नहीं प्रतीत होता। वैश्विक स्तर पर यदि तुलना की जाए तो 139 विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से केवल छह देशों की अर्थव्यवस्थाएं भारत की तुलना में अधिक तेज गति से विकास कर पाई हैं। इसके बावजूद विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत आज भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पाद का आकार सीमित होने के कारण उनकी प्रतिशत वृद्धि दर अधिक दिखाई देती है, किंतु जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे उच्च वृद्धि दर बनाए रखना कठिन होता जाता है। इस संदर्भ में भारत की आर्थिक उपलब्धियां और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विश्व बैंक के आंकड़े यह भी दशार्ते हैं कि वर्ष 1990 में विश्व में निम्न आय श्रेणी के देशों की संख्या 51 थी, जो वर्ष 2024 तक घटकर 26 रह गई है। इसी प्रकार निम्न मध्यम आय श्रेणी के देशों की संख्या भी घटकर 50 रह गई है, जबकि उच्च मध्यम आय श्रेणी के देशों की संख्या बढ़कर 54 और उच्च आय श्रेणी के देशों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। यह परिवर्तन वैश्विक आर्थिक संरचना में हो रहे सकारात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से दशार्ता है। चीन और गयाना जैसे देशों के उदाहरण इस प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करते हैं। चीन वर्ष 1990 में मात्र 330 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ निम्न आय श्रेणी में था, किंतु वर्ष 2010 तक उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 4410 अमेरिकी डॉलर हो गई और वह उच्च मध्यम आय श्रेणी में शामिल हो गया। इसी प्रकार गयाना जैसे छोटे देश ने भी कुछ ही दशकों में निम्न आय श्रेणी से निकलकर उच्च आय श्रेणी में स्थान बना लिया।

Social Media Corner

सच के हक में...

पिछले साल मैं आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया नहीं जा सका था। लेकिन, मैंने अपने मित्र, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा। और अब, 2026 की मेरी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा मलेशिया में हुई। यह यात्रा हमारे देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, सरकार और मलेशिया की जनता के स्नेह के लिए मैं उनका आभारी हूं।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

भारत की उदीयमान युवा शक्ति ने एक बार फिर विश्व मंच पर स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को 2026 विश्व कप विजय पर आज सदन की ओर से हार्दिक बधाई दी गई। हरारे (जिम्बाबवे) में हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को परास्त कर हमारे युवा खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और शानदार टीम-वर्क का परिचय दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने देश के करोड़ों युवाओं में उच्च शिखरों को साधने की नव-प्रेरणा जगाई है।

(ओम बिड़ला का 'एक्स' पर पोस्ट)

झारखंड में डीएमएफटी फंड की लूट और दुरुपयोग की घटनाओं पर संज्ञान लेने के लिए केंद्र सरकार का आभार। खनन प्रभावित क्षेत्रों में गरीब जनता के फेफड़े धूल फांकने और प्रदुषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जबकि डीएमएफटी फंड के पैसे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण में कई जिलों के डीसी अपने बँगले चमका रहे हैं, डाक बंगला बनाकर ऐश-मौज कर रहे हैं और जिम बनाकर फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

योग्यता आधारित नेतृत्व से परिवारवाद को चुनौती

भाजपा के इतिहास में एक नए युग की शुरूआत हुई, जब राष्ट्रीय राजनीति में अज्ञात से नितिन नबीन देश की सबसे बड़ी पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा से वे 20 वर्ष छोटे हैं और अब तक भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। यह पार्टी के रणनीतिक सोच को दशार्ता है, जो भविष्य में नेतृत्व की युवा पीढ़ी तैयार करना चाहती है और संक्रमण काल में प्रधानमंत्री मोदी जैसे वरिष्ठ-अनुभवी तथा नितिन जैसे ऊजार्वान युवा की जोड़ी बनाकर सत्ता की स्थिरता से पार्टी में आने वाले ठहराव और आत्मसंतुष्टि को झकझोरना चाहती है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य स्पष्ट है- 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और उससे पहले विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना। उन्हें इस मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का भान है- लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक रुकावटें, न्यायिक अवरोध, लगातार चुनाव जीतने की चुनौतियां तथा तेजी से बदलता वैश्विक परिदृश्य। नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने कई संदेश दिए हैं। पहला संदेश अपनी पार्टी के लिए ही है कि भाजपा का संगठन अपनी सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी स्वयं नबीन के नामांकन में प्रस्तावक तथा गृहमंत्री एवं रक्षामंत्री अनुमोदक बने, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने उन्हें पार्टी में अपना बॉस बताते हुए कहा कि वे उनकी भी सीआर लिखेंगे और जिस प्रकार अपने स्वागत संबोधन में उन्हें अनेक बार माननीय कहकर संबोधित किया, वह यह संदेश दे गया कि युवा नबीन भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और संगठन के सभी पदाधिकारियों के भी बॉस हैं। ऐसा केवल वही कर सकता है, जो स्वयं कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बना हो। सरकारें तो लोकतंत्र में आती-जाती रहती हैं, लेकिन संगठन हर झंझावात में खड़ा रहता है और रहना चाहिए। यह पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को सख्त संदेश है कि युवा नबीन को कोई भी हल्के में न ले। पार्टी नेतृत्व में यह पीढ़ीगत परिवर्तन भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को संभवतः साकार कर सकेगा। दूसरा प्रमुख संदेश पार्टी ने अपने कार्यकताओं को दिया है कि अपने कार्य, पार्टी की विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता, दलीय कार्यसंस्कृति के प्रति समर्पण एवं जनता से जुड़ाव द्वारा वे संगठन में सर्वोच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका किसी जाति विशेष का होना जरूरी नहीं, किसी राजनीतिक गाडफादर की आवश्यकता नहींझकेवल कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात कर्म प्रधानता के मूलमंत्र का ही ज्ञान होना चाहिए। दुर्भाग्य से देश में अधिकतर पार्टियां परिवार के इर्द-गिर्द घूमती हैं, अतः उनके कार्यकर्ता जनता से जुड़ने के बजाय उस परिवार और उसके मुखिया से जुड़ने को वरीयता देते हैं। उन्हें पार्टी विचारधारा के प्रति समर्पण से ज्यादा जरूरी उस परिवार के प्रति समर्पण लगता है। ऐसा न करने वाले कार्यकर्ता धीरे-धीरे उपेक्षित होकर दूसरी पार्टियों की ओर चल देते हैं। नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकताओं में एक उम्मीद जगी है, जो उन्हें सक्रियता, ऊर्जा, आशा, उत्साह और सकारात्मक सोच से ओतप्रोत कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में महत्वपूर्ण कारक बनाएगी। नवीन को अध्यक्ष बना भाजपा ने तीसरा संदेश राज्य की भाजपा सरकारों को दिया है। करीब 16 राज्यों में भाजपाया राजग सरकारें है। जातिवाद, क्षेत्रीयता और वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा के चलते पार्टियों की राज्य इकाइयों में प्रायः दलीय गुटबाजी होती है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को संतुलित और अनुशासित करना होता है, लेकिन उससे भी जटिल मुख्यमंत्री और राज्य संगठन के शीर्ष नेतृत्व के बीच का संघर्ष होता है। मुख्यमंत्री अपने को बॉस मानता है और प्रदेश अध्यक्ष एक आभूषणीय पद होकर रह जाता है, जो संगठन और सरकार में टकराव को जन्म देता है, जिससे चुनावों में पार्टी की विजय की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं।

राह पर डटे रहें

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को बढ़ावा देने हेतु नियमों को बहुत व्यापक करार देकर उन पर रोक लगा दी। जनवरी में अधिसूचित इन नियमों ने परिसरों में भेदभाव के सभी रूपों, खासकर जाति आधारित, से निपटने की कोशिश की। वर्षों के सक्रियतावाद (एक्टिविज्म), मुकदमेबाजी और राष्ट्र के जमीर को झकझोर देने वाली रोहित वेमुला जैसी दुखद आत्महत्याओं के बाद ये नियम लाये गये। शीर्ष अदालत ने यूजीसी को इन्हें बनाने का आदेश दिया था। इस मुद्दे पर साल 2012 के यूजीसी फ्रेमवर्क को उच्च शिक्षा संस्थानों ने लगभग पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। जाति और जाति आधारित भेदभाव एक हकीकत है जो अब भी बरकरार है और इससे निपटना राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों ने इसे भुगता है, जिससे उन्हें जीवन भर के जख्म मिले हैं और कई बार जिंदगी तक बर्बाद हो गयी है। यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसी शिकायतों की तादाद पिछले पांच सालों में दोगुनी से ज्यादा हो गई है। मसौदा नियम चर्चा के लिए पिछले साल सार्वजनिक किये गये और इन नियमों को बदलावों के साथ अधिसूचित किया गया है। एक दलील यह है कि नए नियमों में साल 2012 के उस फ्रेमवर्क को हल्का कर दिया गया है, जिसमें भेदभाव के कहीं ज्यादा और तुरंत ध्यान देने योग्य रूपों की शिनाख्त की गयी थी, और एससी/एसटी समुदाय के विद्यार्थियों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं, जैसे कि आरक्षण मानदंडों को पूरा नहीं करना, से निपटने के लिए अलग सेक्शन थे। लेकिन नए नियम इस मायने में अलग हैं कि ये समान अवसर केंद्रों, समता कमेटियों, समता हेल्पलाइनों व दस्तों की स्थापना तथा जांच कमेटियों में बेहतर निगरानी, देखरेख और नुमाइंदगी के जरिए समयसीमा के भीतर शिकायत समाधान को लागू करना चाहते हैं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Edit

The Doomsday Clock ticks on

Had the polar chill eased its grip on America's eastern seaboard and if a hydrogen leak had not intervened, Artemis II would have lifted off from Cape Canaveral, US this weekend to put four-member crew in orbit around the moon, a preliminary step to putting astronauts on the lunar surface. The serially-delayed Artemis mission has now been pushed to March. But there is no sense of disappointment in the space industry, the US government or enthusiasts worldwide. What does this signal?Apollo 11, which put the first men on the moon in 1969, was a mission driven by Cold War rivalry. The space race was on, the USSR had put a dog, a man and a woman in orbit, and the US needed to pull a more dramatic stunt. Such a sense of urgency is missing today in a project that initially was to take flight in November 2024.

Perhaps it's because space is no longer a State monopoly and its role as a marker of national prowess is diluted. Perhaps the US doesn't believe it is in a contest, or feels it has anything to prove. That is what the present administration in Washington had said when it sought election, before it became embroiled in tariff wars and other shows of strength. But there's the human factor: what do the majority expect from a moonshot when things are falling apart? Days before the Artemis II launch was deferred, the Doomsday Clock was set forward to 85 seconds to midnight-the closest it has ever been to that hour. The clock, created by the scientists who built the first nuclear weapons, is a visual expression of the proximity of the human race to self-annihilation, graphically represented by the clock striking midnight. In 2025, it was set to 89 seconds to midnight as "national leaders and their societies" had failed to change course away from the precipice. The Doomsday Clock was originally set to seven minutes to midnight in 1947, after World War 2 was ended by nuclear bombings and the colonial era began to unravel. It was advanced to three minutes to midnight in 1949, when the USSR tested its first atom bomb at Semipalatinsk, and it held steady in 1950 despite the Korean War. It was advanced by a minute in 1953, after the US tested a hydrogen bomb at Bikini Atoll and the USSR matched its achievement nine months later.

In the 1960s, as the world agreed upon the importance of limiting nuclear weapons and testing, the clock moved back again to 7 minutes and even 12 minutes to midnight in the early 1970s-marking the end of atmospheric testing and the era of SALT I, the anti-ballistic-missile treaty, and the Nuclear Non-Proliferation Treaty.In 1974, Indira Gandhi ordered the Pokhran I test and the clock jittered forward to nine minutes to midnight. It reached three minutes to midnight in 1984, when the Reagan administration sought space-based anti-ballistic-missile systems. The collapse of the Soviet Union lulled threat perceptions, and the next spike was provided by the Vajpayee government's Pokhran II test in 1998, and Pakistan's answer. The clock was again at nine minutes to midnight, and it was blamed on the leadership failure of the US and Russia in disarmament. The two countries had the largest nuclear weapon inventories. This is still the case, and the clock has again been moved forward due to their leadership failure. Meanwhile, China and India have acquired strategic and economic importance to enter the lists, and their leadership isn't in great health either.Last year, the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists, which sets the Doomsday Clock, had warned of multiple threats facing human civilisation-what the World Economic Forum acknowledges as a 'polycrisis'. They include immediate threats like the US abdicating its leadership responsibility in climate action and choosing fossil fuels. Also, AI companies should have been regulated instead of being treated like freestyle prize-fighters in an international technology tournament. Relatively distant concerns also figured, like 'mirror life', based on molecules that are chirally opposite to those found in nature-such life forms can run amok, but they don't exist yet.

Much ado about a book and a film

THE GREAT GAME: The ability to control information around "strategic affairs" is critical in a democracy

A film and a book have been at the heart of the national debate this week, with Netflix agreeing to change the name and withdraw all promotional material of a film called "Ghooskhor Pandat," or, the Bribe-Taking Pandit, after angry middle-aged men in saffron gear protested the "casteist" slur, an FIR was lodged at the Hazratganj police station in Lucknow, the National Human Rights Commission complained to the Information & Broadcasting Ministry — at the end of which BJP leader Gaurav Bhatia declared victory, saying, "insults to Sanatan Dharma will not be tolerated."

We are committed to taking the strictest possible action against those who demean any caste or community for commercial gains," Bhatia said, adding, "Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas is our guiding principle."It's not clear whether the BJP leader was aware that he was also celebrating the death of irony, apart from squelching the underside of humour. Certainly, slapstick headlines must be removed from fashion.Or perhaps it doesn't matter that much, anymore, not when half the week has been taken up by repeated adjournments in the Lok Sabha. Congress leader Rahul Gandhi has persisted with asking questions over a book written by former Army Chief, Gen Manoj Mukund Naravane. The ruling BJP has stood equally firm, refusing to allow any discussion, arguing that the book has not been published and therefore cannot be debated in Parliament.

What doesn't exist cannot be discussed, right? Except, Rahul has been brandishing a pre-publication copy inside and outside the House. Moreover, the PDF is available for all the world to read. But the government is also right. The book is not available in the market. The Ministry of Defence (MoD) is still checking whether its contents are kosher.Gen Naravane's autobiographical account has some interesting details. These include the India-China standoff in Galwan in Ladakh in June 2020 — when 20 Indian soldiers lost their lives, as did four Chinese soldiers, although foreign news agencies like Russia's Tass said 45 were killed — as well as the action a couple of months later in the Kailash range. There are conversations with Bhutan's influential former King, Jigme Singye Wangchuk, popularly known as K4; messages from Defence Minister Rajnath Singh; as well as meetings with the PM.On the face of it, the paragraph that has lit the political storm is almost harmless, and in fact makes the former Army Chief look a bit out of sorts — a paragraph Rahul is said to have cottoned on to. Which is that when four Chinese PLA tanks were coming towards the Indian soldiers who had taken the Kailash heights, east of Finger 4, Gen Naravane called Raksha Mantri and asked him for orders as to what to do. After some hours, Rajnath Singh is said to have called him back, allegedly after speaking to the PM.In the press note sent by the book publisher more than a year ago, quoted by PTI, Naravane writes, "I conveyed the criticality of the situation to the RM, who said he would get back to me, which he did, by about 2230 hours. He said that he had spoken to the PM and that it was purely a military decision. 'Jo ucchit samjho woh karo' (Do whatever you deem is appropriate). I had been handed a hot potato.

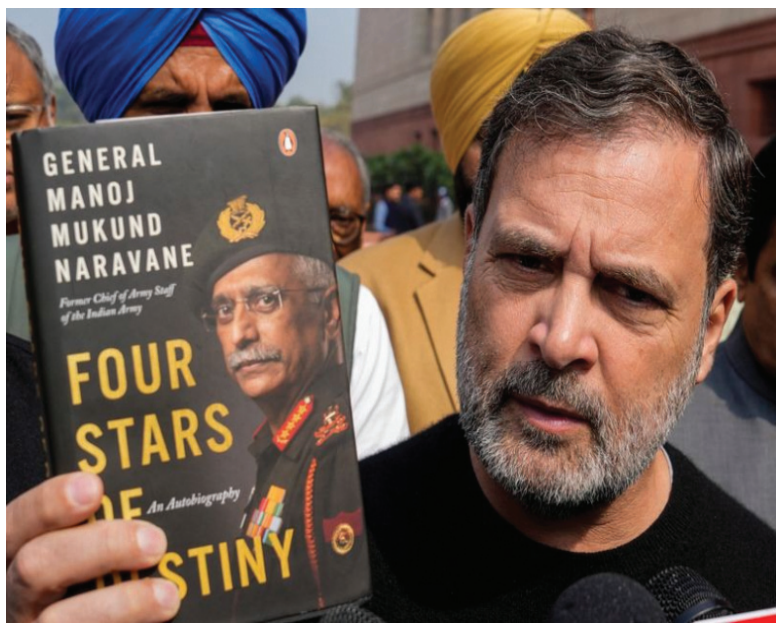

With this carte blanche, the onus was now totally on me. I took a deep breath and sat silently for a few minutes."Come to think of it, isn't that what a Prime Minister or a Defence Minister is supposed to tell his Army Chief? That he's the Chief because he knows best the lay of the land, especially when the enemy is advancing, and therefore he should do what is best by the country.We all know what happens when politics gets involved in military matters, and vice-versa. India's neighbourhood is littered with pretenders in both fatigues and civilian clothes. But everyone knows that in the separation of powers that is the backbone of any democracy, the thumb rules are clear and apparent to both sides.Rahul Gandhi's argument is that national security has been the government's leitmotif since it came to power and that when a crisis took place, in Ladakh in 2020, the PM did not properly advise his Army Chief.

This is certainly a debate worth having. Which is, why were the Chinese able to push you around in Galwan, leading to the death of 20 Indian soldiers? What was the role of the corps commander Lt Gen Harinder Singh in that fracas? How did the Army commander, Lt Gen YK Joshi (Jo, in the book) handle it? What are the lessons learnt from the Galwan tragedy?For sure, national security is a holy cow and operational details can't be revealed — certainly that's why the book has been held by the MoD. But that point has become moot because the book's PDF is now being widely read. Everyone knows what the MoD didn't want known.

Which brings us to the most critical lesson of this teacup storm — because there will doubtless be something else next week — that the ability to control information around that compendium word, "strategic affairs," which is everything from foreign affairs to domestic security, is critical in a democracy. How much to tell the public, is a question every government grapples with. But know that in the Age of Information, despite Donald Trump becoming a bit of an international joke with his 59th claim that he brokered the end of the India-Pakistan conflict at Op Sindoor, the ability to remain credible is at the heart of the argument.

Kargil was a great lesson in what is sometimes called a "media war". Both Op Snow Leopard (the Ladakh face-off) and Op Sindoor, on the other hand, took another tack, which is to shut down the enemy's channels of information — websites, TV and video — and propagate your own. And while that may be necessary when the conflict is kinetic, or live, it can become counter-productive when things return to normalcy.

People are curious, especially when they belong to 5,000-year-old civilisations, and own historical memories around both blood-letting and reconciliation. So when Chief of Defence Staff, Gen Anil Chauhan, admitted to Bloomberg TV that India had lost a fighter jet during Op Sindoor, mere weeks after the end of the operation, the questions followed thick and fast. How many? When? How? What really happened?

Back in the day, when the world was still divided into two power blocs by the Cold War, the former Eastern Bloc had a word called "samizdat", where everything that was banned by the state, whether newspapers or prose or poetry, was copied by hand and distributed amongst the people. Both "Ghooskhor Pandat" and Naravane's book would qualify. Sometimes you wonder if the unfancied PDF is its modern-day version.

Aquifers in peril: Policy correction needed in Haryana

The Tribune Editorial: This is not a sudden failure but the cumulative outcome of policy choices that rewarded extraction while neglecting conservation

HARYANA's groundwater crisis has crossed from warning to emergency. With nearly 64% of the state's blocks now classified as overexploited, extraction far exceeds natural recharge. The situation threatens agriculture, drinking water security and economic stability. This is not a sudden failure but the cumulative outcome of policy choices that rewarded extraction while neglecting conservation. At the heart of the problem lies cropping patterns. Paddy cultivation, promoted through assured procurement and free or subsidised electricity, has locked farmers into a water-intensive cycle in a semi-arid state. Tubewells have replaced canals as the primary irrigation source, pushing aquifers beyond recovery levels. In several districts, groundwater withdrawal has reportedly reached over 130% of the annual recharge, a point that guarantees future scarcity.What makes the condition more alarming is the silent nature of groundwater depletion. Unlike floods or droughts, falling water tables do not command immediate political

attention. The costs emerge gradually — deeper borewells, higher energy consumption, saline intrusion and, eventually, the collapse of farm viability and rural drinking water systems. Urban centres, too, are increasingly dependent on overdrawn aquifers, spreading the risk beyond agriculture.

Policy responses so far have focussed disproportionately on supply-side solutions — recharge structures, ponds and check dams — without addressing demand. Crop diversification away from paddy, rational pricing of electricity, micro-irrigation incentives and enforceable groundwater regulation must move to core policy. Equally important is decentralised governance. Groundwater is a local resource and its management requires community participation, transparent data and district-level accountability. Without empowering panchayats and users to monitor and regulate extraction, state-level targets will remain cosmetic. Unless water is treated as a finite ecological asset, today's overexploitation will translate into tomorrow's water drought. The window for corrective action is narrowing.

From panic to protocol : Tackling bomb scare in schools

Only with parental trust can the system shift from reflexive reaction to assessment-led response in cases of bomb scares in schools.

The bomb scares on January 28 that swept through Chandigarh schools did more than disrupt a school day; it exposed how fragile normalcy has become in the age of anonymous digital threats. Within minutes, Chandigarh's education hub was transformed into a security grid. No explosive device was found. But the absence of a bomb did not diminish the scale of what had occurred. A single anonymous email had succeeded in paralysing the administration, displacing thousands of children, and pushing parents, teachers, and authorities into hours of panic.What unfolded in Chandigarh reflects a wider national and global pattern. Globally, school threats have risen by about 44% over the past two years, yet over 99.8% of mass-emailed threats are hoaxes, creating a paradox in which every message must still be treated as real. Reports from the Ministry of Home Affairs, NCRB classifications, state police briefings and media coverage together suggest a sharp rise since early 2024, with a roughly 300% increase over the past. Law-enforcement reports note the rise of "cluster threats", where identical messages are sent to large numbers of schools within minutes, sharing a clear digital fingerprint and typically routed via encrypted email services and offshore, VPN-masked IP addresses, making attribution difficult.

The magnitude of this drain was also evident a few months back in India's aviation sector, where similar hoaxes imposed a loss of about Rs 600 crore in just nine days. In schools, however, the cost is far harder to measure: it involves children; and for parents, the anxiety cannot be monetised, while the impact appears in lost instructional hours, disrupted board exams, and the logistical nightmare of evacuating tens of thousands of children simultaneously.These incidents have brought two issues into focus: how threats were handled collectively by the city administration, schools and parents, and how communication among them shaped confusion and public anxiety. They also underscore the need to shift from a reactive to a resilient posture, with protocols drafted and enforced at the district level rather than left to individual schools. At least during sensitive periods, precaution must begin well before any threat is received, including decentralised anti-sabotage checks. International best practice supports routine pre-arrival visual sweeps of classrooms, boundary areas, footpaths

and parking zones to establish a baseline of normalcy, making genuine anomalies easier to detect during an incident.Against this backdrop, the debate over school responses to bomb threats has narrowed to two contrasting models: the reflexive 'react-and-assess' approach and the evidence-backed 'assess-and-react' framework. Research shows that react-and-assess, which triggers immediate evacuation before credibility checks, amplifies panic without improving safety. Since over 80% of school bomb threats lack operational specificity, automatic evacuations often push students into open, predictable spaces, creating crowd targets and logistical chaos, with injuries more frequently arising from stampedes and traffic disorder than from explosives themselves.By contrast, the assess-and-react model relies on a brief, structured evaluation, conducted by school authorities in coordination with security agencies, before any large-scale movement. Evidence shows that credible threats contain actionable detail, while mass emails typically do not. Schools using assess-first protocols report fewer unnecessary evacuations, lower disruption and reduced post-incident anxiety, demonstrating that evidence-guided restraint improves both physical and psychological safety.Communication is equally critica. Research shows panic is driven less by the threat itself than by information gaps between administrations, schools and parents. Pynoos et al (2018) found that parental anxiety spikes when no official update is issued within the first 10 to 15 minutes, a reaction intensified by vague messages citing "unforeseen circumstances." Rave Mobile Safety reports that nearly 80% of parents experience peak panic when emergency alerts lack context, triggering gate rushes, identified as the most dangerous secondary risk, where a hoax can act as bait to draw vulnerable crowds outside schools, effectively turning them into sitting targets. In Chandigarh, delayed and opaque communication drew parents to school gates, disrupted traffic and obstructed emergency response vehicles.To mitigate this, research supports a 'strategic transparency' approach using a two-stage alert system. Stage one is an immediate internal alert to police within minutes of a threat. Stage two consists of regular, clear updates to parents during the "Golden Hour," the first 60 minutes, delivered through the school's official app, explaining that a non-specific digital threat is being managed under a controlled protocol. This reduces panic-driven calls, school rushes and communication or traffic congestion, while allowing authorities to operate without crowd pressure. Evidence further shows that post-incident feedback explaining what worked and why decisions were taken reduces residual anxiety and that situation is best managed through staggered school transport rather than chaotic gate pickups.Across research produced by the Educator's School Safety Network, the RAND Corporation, the World Health Organisation's psychosocial risk studies, Cornell University's threat assessment research and guidance from allied security agencies, one consistent finding stands out: reflexive action combined with silence amplifies panic, while assessment-led response supported by clear, timely communication contains it. These bodies converge on the conclusion that proportional decision-making and information flow are as critical to safety as physical security measures themselves.In the Indian context, however, the challenge is not a lack of policing or protocol, but the social ecosystem in which those protocols operate, particularly parental expectations. Schools and administrators function within a deeply ingrained instinct to react first and demonstrate visible action to "make everyone safe", even when the statistical probability of harm is extremely low. This instinct, shaped by collective psychology and public pressure, makes assess-and-react models difficult to sustain unless parents understand and trust the logic behind them. Without parental alignment, administrators default to immediate evacuation to avoid backlash, despite contrary evidence. The present moment is, therefore, the right time to educate parents and treat them as informed stakeholders, because only with their trust and participation can the system shift from reflexive reaction to an assessment-led response, allowing composure, rather than fear, to guide collective action.

Stock markets trade higher in early trade tracking rally in Asian peers

The 30-share BSE Sensex climbed 441.77 points, or 0.53 per cent, to 84,022.17 in the morning trade. The 50-share NSE Nifty rose 129 points, or 0.50 per cent, to 25,822.70.

Mumbai.(Agency)

Equity benchmark indices Sensex and Nifty opened on a positive note on Monday amid foreign fund inflows, a rally in Asian markets and optimism following a fresh trade agreement between India and the US.The 30-share BSE Sensex climbed 441.77 points, or 0.53 per cent, to 84,022.17 in the morning trade. The 50-share NSE Nifty rose 129 points, or 0.50 per cent, to 25,822.70.

Among the 30-share Sensex constituents, State Bank of India, Titan, Eternal, Kotak Mahindra Bank, Bharat Electronics Ltd, Tata Steel, Sun Pharmaceuticals, Larsen & Toubro, Adani Ports, IndiGo, Reliance Industries and Bharti Airtel were the gainers.On the other hand, PowerGrid, ITC, Hindustan Unilever, Bajaj Finance, Trent, Infosys, ICICI Bank, Axis Bank, NTPC, Tech Mahindra, Tata Consultancy Services, HDFC Bank were among the laggards.Foreign institutional investors bought equities worth Rs 1,950.77 crore on Friday, according to exchange data.

"A big positive for the market is that FIIs who were sustained sellers in the market have bought in the cash market in three out of the last four trading days. The fact that the derivatives market continues to be heavily net short might impart resilience to the market, on expectations of short covering," VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Ltd, said.He added that the recent 'Anthropic shock' will continue to impact sentiments in the IT sector.

On the contrary, banking stocks are likely to gather strength on news of improving credit growth, which will have positive fall out for GDP growth and corporate

earnings in FY27.In Asian markets, Japan's Nikkei 225, South Korea's Kospi, Shanghai's SSE Composite index and Hong Kong's Hang Seng index trading higher.Devarsh Vakil, Head of Prime Research, HDFC Securities said Japan's ruling Liberal Democratic Party, led by Sanae Takaichi secured a decisive victory pushing the Nikkei to record highs.

He noted that Indian equities stand to gain as Japanese capital pivots away from China under Takaichi's "Economic Security" policy, with billions in FDI expected to flow into Indian infrastructure and technology sectors, he said.Vakil further said India and the US on Saturday reached an interim trade agreement ending their ten-month tariff war, with Washington reducing tariffs on Indian goods from 50 per cent to 18 per cent.India successfully protected sensitive agricultural sectors like dairy while committing to purchase USD 500 billion in US goods over five years, focusing on energy, aircraft, and defence technology.The deal strategically integrates India into the US-led "Pax Silica" initiative for critical minerals and AI supply chains, positioning India as a counterweight to China in the Indo-Pacific, he added.

US markets ended more than 2 per cent higher on Friday. Brent crude, the global oil benchmark, declined 0.94 per cent, to USD 67.41 per barrel.On Friday, the 30-share BSE Sensex advanced 266.47 points to settle at 83,580.40, while the NSE Nifty climbed 50.90 points to end at 25,693.70.

Adani Energy secures Japanese funding for 6,000 MW green power project

Mumbai.(Agency)

Adani Energy Solutions Ltd (AESL) has raised long-term funding from a group of Japanese banks for its flagship high-voltage direct current (HVDC) transmission project, the company said in a press release. The project is designed as a green evacuation corridor to support the growing movement of renewable power across northern India.

The HVDC project will play a vital role in evacuating renewable energy from Rajasthan, one of India's most solar-rich states, and feeding it into the national grid. This will help ensure that green power generated in remote regions can reach areas with high electricity demand.

Built as a ±800 kV HVDC system, the corridor will have an evacuation capacity of 6,000 megawatts (MW). Spanning about 950 km, it will connect Bhadla in Rajasthan to Fatehpur in Uttar Pradesh. The project is scheduled to be commissioned by 2029. Once operational, the transmission link is expected to become a major green power artery, helping integrate large volumes of renewable energy while improving grid stability for energy-intensive cities and industrial hubs in northern India. Kandarp Patel, Chief Executive Officer (CEO), AESL, said, "This project marks a defining step in building India's green transmission backbone. The continued support from our Japanese partners -- including leading banks and Hitachi -- reflects the depth of the India–Japan partnership and our shared commitment to enabling a sustainable energy future..."

Adani Group's clean energy ecosystem

The transmission asset is part of the Adani Group's broader clean energy platform. Rajasthan remains a key generation base for Adani Green Energy Limited (AGEL), whose renewable projects already supply power to AESL's subsidiary, Adani Electricity Mumbai Limited (AEML), the press release said.

AEML currently sources over 40 per cent of its electricity from renewable energy, placing Mumbai among the world's major cities with significant green power usage. India-Japan collaboration

The funding has been led by Japanese banks MUFG Bank Ltd and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Gold price prediction today: Will gold prices continue to be volatile in the near term Check outlook

New Delhi.(Agency)

Gold price prediction today: Gold prices are likely to remain volatile this week, says Manav Modi, Senior Analyst, Commodity Research at Motilal Oswal Financial Services Ltd. The expert shares his outlook for gold prices in the near term:

Gold and silver witnessed another volatile yet constructive last week, with prices rebounding sharply after aggressive liquidation at the start of this month, as forced unwinding eased and value buying emerged across both metals. The earlier correction—triggered by a sharp dollar rebound, shifting Fed expectations, easing geopolitical risk premiums and heavy speculative positioning—appears to have run its course for now, allowing bullion to stabilise and recover.

Gold rebounded decisively from the ?141,000 zone, forming a clear V-shaped recovery on daily charts, while prices continue to sustain well above the key momentum pivot of ?138,000, keeping the broader trend positive. Bollinger Bands, which had compressed during the correction, have begun to expand again with prices moving towards the upper band, signalling a revival in directional strength supported by improving volumes.

Immediate support for gold is seen near ?150,000 followed by ?143,000, while the earlier target of ?155,000 has been achieved; any sustained close above this level could open the path towards ?165,000 and ?171,000 from a short to medium-term perspective.Despite a relatively firm dollar and lingering policy uncertainty, safe-haven demand remains underpinned by central-bank buying, renewed geopolitical and fiscal concerns. Domestically, a rebound in USDINR from recent lows has lent support to MCX prices.

Cuba halting airline refueling as US punishment takes toll

New Delhi.(Agency)

Cuba has warned airlines it is suspending jet fuel supplies for a month because of an energy crisis prompted by the US attack on Venezuela, an official at a European carrier said Sunday.

Cuba has told carriers serving the communist-run island that starting midnight Monday into Tuesday they cannot refuel there, the official told AFP on condition of anonymity.Cuba is reeling from a US-ordered halt in oil shipments from Venezuela after Amrican troops captured Nicolas Maduro.

Planes covering long-distance flights from Cuba will now have to stop somewhere after leaving the island to get more jet fuel, this official quoted Cuban aviation officials as saying.Air France told AFP its planes would stop somewhere else in the Caribbean to refuel.The Cuban government on Friday announced emergency measures to address the island's energy crisis, including a four-day work week for state-owned companies and fuel sale restrictions.The belt tightening measures include a reduction in bus and train services between provinces and the closure of certain tourist establishments.School days will also be made shorter and universities will relax requirements on in-person attendance.

Washington has increased pressure on Cuba's communist government in recent weeks.

The United States cut off oil deliveries from Havana's key ally Venezuela following its ouster of Maduro in early January.President Donald Trump also signed an executive order allowing his country to impose tariffs on countries selling oil to Havana.

SBI share price jumps 6% to hit 52-week high. Here's why and if you should buy

New Delhi.(Agency)

Shares of State Bank of India rose sharply on Monday, jumping over 6% to hit a fresh 52-week high of Rs 1,136.85. The stock was trading at Rs 1,130.90, up Rs 64.50 or 6.05% from the previous close of Rs 1,066.40 as oif 10:10 am.

With this move, SBI emerged as the top gainer on Sensex in early trade and recorded its biggest single-day gain since June 2024. The rally came after the bank reported strong third-quarter results, which were better than market expectations.SBI shares have been on a steady rise over the past year. The stock has gained 7.54% in the last five trading sessions and 13.04% over the past one month. Over six months, the shares are up 37.35%, while the one-year gain stands at 53.50%.During Monday's session, the stock opened at Rs 1,120, touched a high of Rs 1,136.85 and a low of Rs 1,100.60. The volume-weighted average price for the day was Rs 1,126.26. The stock is now trading close to its upper price band of Rs 1,173, while the lower price band stands at Rs 959.80.

WHY SBI SHARES ROSE TODAY

The main reason behind the sharp rise was SBI's strong performance in the December quarter. The bank reported a 24% growth in net profit, beating

market estimates. It also outperformed large private sector banks such as ICICI Bank and HDFC Bank in loan growth during the quarter.SBI also raised its guidance for the next financial year, which added to investor confidence. Analysts said this showed better visibility on growth and earnings at a time when concerns remain around credit growth in the banking sector.

CLSA said sequential loan growth at SBI was much better than other public sector banks as well as large private banks. This pointed to stronger demand and better execution by the bank.

CITI said margins are expected to remain at or above 3%. It added that disciplined lending practices, along with recoveries, should support healthy asset quality in the coming quarters.

Nuvama noted that SBI's core earnings have been stronger than private banks for the third straight quarter. It highlighted stable net interest margins, loan growth higher than the sector average and strong fee income as key positives.Bernstein said the combination of strong growth, improved margins and better asset quality has kept return on assets above the 1% mark and return on equity above 20%.

Why Aadhaar biometrics locking matters How to do it in just few simple steps Explained

New Delhi.(Agency)

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) gives Aadhaar card holder the facility for Biometric Locking and Unlocking. It is a service that allows an Aadhaar card holder to lock and temporarily unlock their biometrics.

What happens with Biometric Locking?

Once the biometric locking service is availed, fingerprint, iris and Face as a biometric moadlity will be locked. Aadhaar holder will not be able to perform the Aadhaar authentication using the biometric modalities thereafter.Locked Biometrics confirms that Aadhaar holder will not

be able to use Biometrics (fingerprints/iris/Face) for authentication, it is a safety feature to stop any kind of biometric authentication. It also ensures that any entity by any means cannot perform biometric based Aadhaar authentication for that Aadhaar holder.Once Aadhaar number holder enables Biometric Locking system their biometric remains locked till the Aadhaar Holder choses to either Unlock it (which is temporary) or Disable the Locking system.

How can biometric unlock be done?

The biometric unlock can be done by Aadhaar card holder either by visiting UIDAI website, enrolment centre, Aadhaar Seva Kendra(ASK), through m-Aadhaar.It must be noted that registered Mobile Number is essential to avail biometric unlock service. In case your mobile number is not registered with Aadhaar visit the nearest Enrolment Centre/Mobile Update End Point.Why Aadhaar biometrics locking matters? Aadhaar number holders who have registered mobile number may lock their biometrics. This facility aims to strengthen privacy and confidentiality of Aadhaar number holder's Biometrics Data. After locking biometrics if a UID is used for invoking any of the Authentication services using a biometric modality (Fingerprint/Iris/Face) a specific error code '330' indicating biometrics are locked will be displayed and the entity will not be able to perform the biometric authentication.

How is the digital shift changing UAE real estate for investors

New Delhi.(Agency)

The UAE real estate market has long been defined by speed, scale, and global appeal. What has changed in recent years is how demand is formed and validated.Investor decisions are now increasingly shaped upstream through digital discovery, data-led targeting, and algorithmic visibility well before a site visit or broker engagement occurs.

Search behaviour, platform recommendations, virtual property experiences, and digitally surfaced trust signals have become central to how capital flows into the market.

FROM PAPERWORK TO PLATFORMS

Real estate transactions in the UAE have rapidly moved from manual processes to digital-first systems. Government-backed platforms now allow buyers to verify property ownership, register transactions, and complete transfers online.In Dubai alone, more than 90% of real estate transactions are processed digitally, significantly reducing processing time and minimising fraud risk.This digitisation has supported record-breaking activity. According to publicly available market data, Dubai has consistently reported hundreds of thousands of property transactions annually, with transaction values running into hundreds of billions of dirhams in recent years.

For investors, particularly international buyers, this means faster deal execution, clearer audit trails, and reduced dependency on intermediaries.

DATA IS BECOMING THE NEW ASSETOne of the most important changes is how data now informs decision-making. Investors no longer rely solely on broker insights or historical averages.Digital dashboards provide real-time visibility into pricing trends, rental yields, demand by neighborhood, and future supply pipelines.Prime residential areas in the UAE continue to offer rental yields averaging between 5% and 8%, placing the region among the more competitive global real estate markets.Beyond yield, platforms increasingly capture intent data, what investors search for, compare, and shortlist before engaging.From a digital marketing perspective, this has transformed real estate into a demand-led funnel rather than a purely broker-driven process.

How Norway turned oil into a $2 trillion fund that may never run out

Norway is more often known as one of the happiest countries in the world which has the best Northern Lights, not as a financial powerhouse. Yet behind this image of calm and comfort sits one of the most powerful financial institutions on the planet.

New Delhi.(Agency)

When people think of Norway, they usually picture snow-covered landscapes, long winters, fjords, the Northern Lights dancing across dark skies, and stories of Vikings. Norway is more often known as one of the happiest countries in the world, not as a financial powerhouse. Yet behind this image of calm and comfort sits one of the most powerful financial institutions on the planet.Norway discovered oil in the North Sea in 1969, the country faced a question that many resource-rich nations struggle with. How should sudden wealth be used without damaging the economy or short-changing future generations?

Norway's answer was not speed or scale, but restraint. Over time, that choice led to the creation of a financial institution that now stands among the most powerful investors in the world.Today, the Government Pension Fund Global is worth more than 21.2 trillion Norwegian kroner, or over $2 trillion, which is almost half of India's GDP.It is not just a store of oil money. It is a long-term financial engine designed to support the Norwegian economy long after oil production fades.

WHY THE FUND WAS CREATED

Oil revenues transformed Norway's economy quickly after the discovery of large offshore reserves. Growth accelerated, and state income rose sharply. But policymakers were also aware of the risks. Oil prices are volatile, and oil itself is a finite resource.To avoid sharp swings in the economy and protect national wealth, Norway decided early that oil income should be used cautiously. In 1990, parliament passed legislation to establish what later became the Government Pension Fund Global.The first transfer into the fund was made in

1996, once the government began running consistent surpluses from petroleum revenues.The goal was clear. Oil wealth would be saved and invested so that both present and future generations could benefit, even after oil and gas production declines.

WHY THE MONEY IS INVESTED OUTSIDE NORWAY

A key decision was to invest the fund entirely abroad. This helped prevent excessive spending at home and reduced pressure on prices, wages, and the currency.As a result, the fund evolved into a global investor. As of the end of 2025, it had investments across 68 countries and more than 10,200 individual holdings.The fund now owns close to 1.5 percent of all shares in the world's listed companies, giving it exposure to global growth rather than domestic cycles alone.

WHAT THE FUND OWNS TODAY

Equities form the backbone of the fund. Shares account for about 71 percent of its total value, worth more than 15.1 trillion Norwegian kroner.These equity investments span roughly 7,200 companies across 60 countries, giving the fund small stakes in businesses across sectors and regions.

Fixed income investments make up around 26.5 percent of the portfolio, valued at about 5.6 trillion Norwegian kroner. These include bonds issued by governments and companies in 48 countries, providing steady income and lower risk compared to equities.The fund also owns real assets. It holds 1,389 real estate investments across 14 countries, valued at roughly 372 billion Norwegian kroner. In addition, it has invested in renewable energy infrastructure projects in five countries, though this remains a small share of the overall portfolio

Who is Lamborghini crash accused Shivam Mishra, tycoon's son linked To 2024 I-T raids?

A high-speed Lamborghini crash in Kanpur has brought Shivam Mishra and his family business, Banshidhar Tobacco Group, back into the national spotlight amid ongoing controversies.

New Delhi.(Agency)

A high-speed Lamborghini crash in Uttar Pradesh's Kanpur has once again brought Shivam Mishra and his father K K Mishra, owner of the Banshidhar Tobacco Group, into national focus, reviving attention on a business family that has figured prominently in recent controversies.

The Mishras head one of the country's major tobacco suppliers. K K Mishra leads the Kanpur-based Banshidhar Tobacco Group, a key raw material provider to several leading pan masala and tobacco brands. While rooted in Uttar Pradesh, the group's commercial presence extends across Delhi, Mumbai, Gujarat and other states.

A LEGACY BUSINESS WITH NATIONAL REACH

Established nearly 90 years ago, Banshidhar Tobacco is counted among Kanpur's oldest industrial houses. Over decades, it has emerged as a significant player in the tobacco supply chain, servicing some of the biggest names in the industry.

In recent years, Shivam Mishra has taken on a central role in the company's operations. Widely regarded as the face of its current management, he is involved in key decisions related to expansion, production and overall strategy, driving the group's national growth.

INCOME TAX RAIDS AND SUDDEN PROMINENCE

The group entered the national spotlight in March 2024 after the Income Tax Department conducted searches at more than 20 locations linked to Banshidhar Tobacco Group and its promoters.

The operation covered multiple states, including Uttar Pradesh, Delhi, Mumbai and Gujarat.

During the searches, officials claimed to have recovered large amounts of cash, documents related to luxury vehicles and high-value diamond watches from premises associated with Shivam Mishra, including his residence in Delhi. Investigators alleged evidence of tax evasion amounting to crores of rupees and undisclosed assets, bringing Shivam Mishra widespread attention.

WHO IS SHIVAM MISHRA

Shivam Mishra is a director at Banshidhar Tobacco Private Limited and oversees the company's daily functioning. He operates between Kanpur and Delhi's Vasant Vihar area. Within the organisation, he handles manufacturing, supply chain management and financial planning, and has played a key role in expanding the group's footprint across India.

CONTROVERSY DURING RAIDS

Another episode during the income tax action added to the controversy. Officials alleged that a licensed pistol was briefly pointed at them by Shivam at the Delhi residence before their identity was clarified and the situation brought under control. After identifying themselves as Income Tax Department officials, Shivam calmed down, putting his arm away. The incident drew considerable attention at the time.

A TASTE FOR LUXURY

Shivam Mishra is also known for a luxury-heavy lifestyle. Reports have linked him to ownership of several high-end vehicles, including Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, McLaren and Porsche. He is also said to possess a collection of diamond jewellery and premium watches valued at crores of rupees.

Labourer held days after biker's death in Delhi Jal Board pit

New Delhi.(Agency)

Delhi Police on Sunday apprehended a labourer from Firozabad in Uttar Pradesh in connection with the death of a 25-year-old biker who fell into an uncovered 15-foot-deep pit dug for sewer work in west Delhi's Janakpuri, officials said.

The labourer allegedly fled the spot without informing the police or emergency services. The subcontractor involved in the project has already been arrested.The labourer, identified as Yogesh, was apprehended for allegedly failing to report the incident to the authorities and for misleading the victim's family when they arrived at the spot searching for him, an officer said.

"Yogesh informed the sub-contractor, Rajesh Kumar Prajapati, about the incident during the night but did not alert the police or any emergency agency. When the victim's family reached the spot later that night, Yogesh misled them," the officer said. The duty magistrate granted one day of police custody to Prajapati for further probe, he added.According to police, an eyewitness first informed a guard stationed near the site that someone had fallen into the pit. The guard then informed Yogesh, who subsequently alerted Prajapati. However, no information was shared with the police at that time. Police were finally informed around 8 am on Friday after receiving a PCR call from a woman, by which time the biker had already died.

DCP (West) Darade Sharad Bhaskar said sub-contractor Rajesh Kumar Prajapati was arrested under Section 105 (culpable homicide) of the BNS. "Based on technical surveillance, we identified eyewitness Vipin Singh, who saw the motorcycle fall into the pit and alerted a guard," Bhaskar said.

Supreme Court sends Unnao rape convict Kuldeep Sengar back to High Court

New Delhi.(Agency)

The Supreme Court on Monday asked the Delhi High Court to give an "out-of-turn" hearing to former Uttar Pradesh MLA Kuldeep Singh Sengar's appeal against his conviction and 10-year sentence in the custodial death case of the Unnao rape victim's father, and said the matter should be decided within three months.

The Court directed that the victim's appeal seeking enhancement of Sengar's sentence be heard together with his appeal.

A Supreme Court bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice N V Anjaria heard a petition filed by former MLA Kuldeep Singh Sengar challenging the Delhi High Court's January 19 order refusing to suspend his sentence in the custodial death case.

Senior Advocate Siddharth Dave, appearing for Sengar, submitted that he has already served 7 years and 7 months of actual imprisonment out of the 10-year sentence.Solicitor General Tushar Mehta, representing the CBI, informed the court that the main appeal against Sengar's conviction is listed for hearing on February 11, 2026, and suggested it be taken up expeditiously on an out-of-turn basis.

Advocate Mahmood Pracha, appearing for the victim, submitted that an appeal has been filed seeking conversion of Sengar's conviction from Section 304 IPC to Section 302, which would entail enhancement of the sentence to life imprisonment.

Senior Advocate Siddharth Dave argued that in cases involving a fixed-term sentence, suspension of the sentence during the pendency of an appeal is generally the norm. However, the bench observed that Sengar is already serving a life sentence in a separate case related to the rape of the Unnao girl.

'Delhi will become Khalistan': Students evacuated after at least 15 city schools, Parliament get bomb threat mail

New Delhi.(Agency)

At least 15 schools in the national capital and the Parliament received bomb threat emails on Monday, prompting a massive security response, the Delhi Fire Services (DFS) said.According to the DFS, emergency calls were received from multiple educational institutions across different parts of the city in the morning, following which fire tenders and bomb disposal teams were rushed to the locations.

Of these, eight threats were later declared

hoaxes, officials said."A total of 15 schools received bomb threats today. Fire service teams immediately reached the premises. Checking is underway," a DFS official said.

A screenshot of the mail doing rounds on the social media read, "Delhi will become Khalistan. In memory of Afzal Guru." The mail also threatened of a blast in the Parliament on February 13 at 1.11 pm.

The schools included Loreto Convent School in Delhi Cantonment, Cambridge School, Srinivaspuri in South Delhi, Venkateshwar School, Rohini in North West Delhi, CM School and Bal Bharati School in Rohini, Cambridge School, New Friends Colony in South Delhi, The Indian School, Sadiq Nagar in South Delhi and DTA School, INA.

The schools were evacuated as a precautionary measure. Bomb detection and disposal squads, along with dog squads, are carrying out extensive searches.

Senior police officers said cyber teams have been pressed into service to trace the origin of the email, while security arrangements across sensitive locations in the capital have been reviewed.No suspicious object has been recovered so far from any of the school premises, officials said, adding that searches were continuing and further details were awaited.

Student shoots classmate dead, then turns gun on himself at Punjab college

New Delhi.(Agency)

A student shot and killed his woman classmate at a college in Punjab's Tarn Taran district on Monday before turning the gun on himself. The shooting was captured on the classroom's CCTV camera.

The incident occurred at Mai Bhago Law College in Usma. The shooter was identified as Prince Raj, a resident of Mallian village, while the woman was identified as Sandeep Kaur, of Naushehra Pannuan. Kaur died on the spot, while Prince Raj is critical and undergoing treatment, a senior police official said.

CCTV footage shows Prince Raj walking into the classroom with a bag slung over his back. He approaches Kaur and another woman classmate, speaking briefly with them. The three then move to seats at the back of the classroom and continued talking.

Moments later, the video shows Prince Raj abruptly standing up and opening his bag with his back to the two women. He pulls out a gun, turns around and shoots Kaur point-blank. Kaur collapses to the floor as the other classmate recoils in shock. Prince Raj then puts the gun to his temple and fires, crumpling to the ground.Students inside the classroom can be seen panicking and running out of the room immediately after the shots were fired, the footage shows.

A senior police official said the incident transpired just as classes were about to begin. Sandeep Kaur's body was sent for post-mortem.

The motive behind the shooting was not immediately known. Senior police officials said footage from CCTV cameras is being examined as part of the investigation.

Sandeep Kaur's mother questioned how Prince Raj was allowed to walk into the college with a gun. She demanded the strictest action be taken against him.Further details are awaited.

500 new e-buses launched in Delhi, CM Rekha Gupta says 14,000 by 2028

New Delhi.(Agency)

The Delhi government on Sunday launched 500 electric buses, taking the total electric vehicle (EV) fleet of the Delhi Transport Corporation (DTC) to over 4,000, Chief Minister Rekha Gupta said.She added that the government aims to increase the total number of electric buses to 7,500 by the end of 2026 and expand the DTC fleet to 14,000 buses by 2028.

"This step will not only boost transportation and connectivity in the city but will also help reduce air pollution. These EV buses will improve air quality while

meeting the transport needs of Delhi. They are air-conditioned, low-floor buses equipped with panic buttons and other modern features," the Chief Minister said at the launch event, which was attended by BJP National President Nitin Nabin.

Gupta said that for the first time in Delhi's history, 500 electric buses had been inducted into the public transport system at one go, making the capital the city with the largest electric bus fleet in the country. She also announced the launch of a new electric bus route between Delhi and Panipat to provide safe, convenient and pollution-free travel.

Meanwhile, the Chief Minister said the Delhi government has approved a grant of Rs 1,200 crore for DTC. Of this, Rs 1,100 crore has been earmarked for payment of salaries, pensions and statutory dues of DTC employees and pensioners.

The remaining Rs 100 crore will be used for developing an advanced traffic management system and commercial EV charging infrastructure, the officials said."The grant reflects our commitment to the dignity and financial security of DTC employees and pensioners," Gupta said, adding that the initiatives align with the government's vision of a clean, technology-driven public transport system.

Ghaziabad sisters' suicide: Father's lies about third wife surface amid probe

New Delhi.(Agency)

The investigation into the deaths of three minor sisters who jumped from the ninth floor of a high-rise in Ghaziabad is getting murkier, with police uncovering contradictions in their father's statements, unclear marital ties, and troubling details about the children's lives at home and school.

With every round of questioning, police say new details are emerging about the girls' father, Chetan Kumar, his three marriages, shifting statements, money troubles and the life the children were living behind closed doors.

A WOMAN CALLED TINA, AND TWO DIFFERENT STORIES

Chetan told police that in 2018 he worked in Ghaziabad arranging credit card services. During that time, he hired a young woman named Tina. According to police sources, the two later grew close and Chetan married her, making Tina his third wife.

Tina is believed to be around 22 years old and has a three-year-old daughter with him. What has puzzled investigators is that Chetan had earlier told police that Tina was not his wife but his sister-in-law. This contradiction has now become a key part of the probe.

THREE MARRIAGES, AND A TIMELINE THAT DOES NOT FIT

Chetan has admitted that he married Sujata in 2010 and Hina in 2013. But police say the timeline raises questions. His eldest daughter from Sujata is 16 years old, which casts doubt on his claim that he married again because his first marriage did not result in children.

Police are now trying to verify the sequence of marriages through documents. This has been difficult, as both Sujata and Hina are illiterate and have been unable to provide marriage dates or paperwork.

A THREE-BEDROOM FLAT, BUT ONE ROOM FOR EVERYONE

Another detail that has drawn police attention is the family's living arrangement.

Despite living in a three-bedroom flat, the entire family slept in a single room.When asked how the three girls managed to leave the room late at night without anyone noticing, Chetan reportedly told police that it was part of their usual routine. Investigators say this explanation has raised more questions than it has answered.

SCHOOL STOPPED, CHILDHOOD CUT SHORT

Police questioning has also revealed that the girls had not gone to school for several years. The family has blamed financial hardship for stopping their education.

Officers are now trying to find out which schools the girls attended earlier, how much they studied and what led them to drop out. Police will also check claims that the girls were weak in their studies or failing repeatedly.

PHONES SOLD, SILENCE LEFT BEHIND

Police have found that the girls had two mobile phones earlier. Chetan sold both due to debt, one around six months ago and the other just 15 days before the incident.

NEWS BOX

France's former culture minister resigns over Epstein-linked tax fraud investigation

PARIS. (Agency)

France's former Culture Minister Jack Lang has resigned as head of a Paris cultural center over alleged past financial links to convicted sex offender Jeffrey Epstein that prompted a tax investigation.He is the highest-profile figure in France impacted by the release of Epstein files on January 30 by the U.S. Department of Justice. He is known for his role as a culture minister under Socialist President François Mitterrand in the 1980s and 1990s.Lang, 86, was summoned to appear at the French Foreign Ministry, which oversees the Arab World Institute, on Sunday, but he submitted his resignation.He "is very sad and deeply hurt to be leaving a position he loves," his lawyer Laurent Merlet said Sunday on RTL radio.

"He put the interests of the Arab World Institute first," Merlet said, adding that his client denied the allegations and called them inaccurate.The Foreign Ministry confirmed his resignation Saturday evening.The financial prosecutors' office said it had opened an investigation into Lang and his daughter, Caroline, over alleged "aggravated tax fraud laundering."French investigative news website Mediapart reported last week on alleged financial and business ties between the Lang family and Jeffrey Epstein through an offshore company based in the U.S. Virgin Islands in the Caribbean Sea.

Jack Lang's name was mentioned more than 600 times in the Epstein files, showing intermittent correspondence between 2012 and 2019. His daughter was also in the released files.

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's party secures supermajority in lower house in landslide victory

TOKYO. (Agency)

The governing party of Prime Minister Sanae Takaichi secured a two-thirds supermajority in a key parliamentary election Sunday, Japanese media reported citing preliminary results, earning a landslide victory thanks to her popularity.

Takaichi, in a televised interview with public television network NHK following her sweeping victory, said she is now ready to pursue policies that would make Japan strong and prosperous.

NHK, citing results of vote counts, said Takaichi's Liberal Democratic Party, or LDP, alone secured 316 seats by early Monday, comfortably surpassing a 261-seat absolute majority in the 465-member lower house, the more powerful of Japan's two-chamber parliament. That marks a record since the party's foundation in 1955 and surpasses the previous record of 300 seats won in 1986 by late Prime Minister Yasuhiro Nakasone.

A smiling Takaichi placed a big red ribbon above each winner's name on a signboard at the LDP's headquarters, as accompanying party executives applauded.Despite the lack of a majority in the other chamber, the upper house, the huge jump from the preelection share in the superior lower house would allow Takaichi to make progress on a right-wing agenda that aims to boost Japan's economy and military capabilities as tensions grow with China and she tries to nurture ties with the United States.

Takaichi said that she would firmly push forward her policy goals while trying to gain support from the opposition.

How Jamaat-BNP Contest Will Decide Bangladesh's India, China Ties

Dhaka. (Agency)

Bangladesh is holding its most important election in recent times this week, and the two main parties, the Bangladesh Jamaat-E-Islami and the Bangladesh Nationalist Party (BNP), are leaving no stone unturned to engage with the voters amid a tight contest. For years, under ousted premier Sheikh Hasina's rule, the opposition in the South Asian country had little presence on the streets during polls, either boycotting them or being sidelined by mass arrests of senior leaders.

Now, ahead of Thursday's vote, the roles have reversed. With the official deadline for the end of campaigning at 7:00 am on Tuesday, Monday is the last chance for parties to reach out to voters. With Hasina's ouster and the subsequent ban on her party-- Awami League-- by the Muhammad Yunus-led interim government, Bangladesh saw the emergence of once allies Jamaat and BNP as the principal players in its politics.

The Bangladesh Nationalist Party (BNP) is widely expected to win, although a coalition led by the Islamist Jamaat-e-Islami is putting up a strong challenge. A new party driven by Gen-Z activists under the age of 30 has aligned with Jamaat after failing to translate its anti-Hasina street mobilisation into an electoral Analysts believe Jamaat may spring a surprise, as the party is expected to post its best-ever performance in the February 12 polls. Jamaat gained a position of strength following the overturn of the ban on its activities soon after the Yunus government took over in 2024, and its subsequent return to politics with the Election Commission in Bangladesh restoring its registration.However, the return of Tarique Rahman to the country after 17 years in political exile has reinvigorated the BNP cadre. The death of former Prime Minister Begum Khaleda Zia has also created a sentiment in favour of the BNP. This situation has made this election a tight contest, with the Jamaat and the BNP taking potshots at each other during the campaign rallies.

Singapore's Tamil news presenter gets lifetime achievement award

The prestigious accolade recognises her remarkable contributions to Tamil broadcast journalism in a career that has spanned over four decades and left an indelible mark on Singapore's media landscape.

SAN DIEGO. (Agency)

Singaporean news presenter Pavalakantham Azhagarsamy has received the Lifetime Achievement Award at Mediacorp's Pradhana Vizha 2026 in recognition of her contributions to Tamil broadcast journalism in Singapore.The prestigious accolade recognises her remarkable contributions to Tamil broadcast journalism in a career that has spanned over four decades and left an indelible mark on Singapore's media landscape.The award was presented during the 21st edition of the annual ceremony, which honours excellence in Singapore's Indian entertainment, said Mediacorp in a news release on Sunday."As a respected news presenter, mentor and industry stalwart in a career spanning more than four decades, she continues to mentor new generations of Tamil media professionals in the radio and television industry in Singapore today," said Singapore's national media network.

The event, held at The Theatre at Mediacorp on Saturday, featured 19 awards across performance and programme categories, celebrating outstanding achievements in television, audio and digital content.The night also saw horror drama Karuvanam emerging as a huge winner with five awards, including Best Actor, Best Supporting Actor and Best Supporting Actress, while mystery drama Pithamagan was named Best Drama Series.The audience also had a say, casting their votes for the most popular male and female personalities.Winners Guruu and Nisha Kumar were crowned fan favourites, having won the hearts of the fans.Mediacorp's chief customer and corporate development officer Angeline Poh said: "Pradhana Vizha 2026 has brought together talents across generations in a compelling showcase of production excellence, while celebrating the achievements of those who dared to dream.

"As the ceremony marks its 21st edition, it not only reflects how far the industry has come, but also signals the exciting future ahead," Channel News Asia quoted Poh as saying.

New Zealand's Christchurch mosque killer appeals against life imprisonment without parole

WELLINGTON. (Agency)

A white supremacist who shot and killed 51 people at two New Zealand mosques in 2019 launched an appeal Monday seeking to overturn his conviction.Brenton Tarrant, an Australian former gym instructor, admitted carrying out New Zealand's deadliest modern-day mass shooting before being sentenced to life in jail in August 2020.But the convicted killer now argues "torturous and inhumane" detention conditions during his trial made him incapable of making rational decisions when he pleaded guilty, according to a court synopsis of the case.Tarrant is being held in a specialist unit for prisoners of extreme risk at Auckland Prison, seldom interacting with inmates or other people.He appeared in the Court of Appeal in Wellington via video link, his head shaved and wearing black glasses and a white button-up shirt.

"I did not have the mind frame or mental health required to be making informed decisions at that time," Tarrant told the court, according to the New Zealand Herald.Tarrant said his state of mind was such that he had considered trying to implicate US President Donald Trump in the crime.Life without parole"What I said at the time is 'perhaps I could go out and say there was a second shooter on the roof, perhaps I could say it was Donald J Trump'," he said, according to national broadcaster RNZ.If the Court of Appeal in Wellington upholds Tarrant's conviction, it will also need to consider an appeal against his sentence.If his conviction is overturned the case will be sent to the High Court for a retrial.His penalty of life imprisonment without parole was the stiffest in New Zealand history.Armed with an arsenal of semi-automatic weapons, Tarrant attacked worshippers at two mosques in Christchurch on March 15, 2019.

He published an online manifesto before the attacks and then livestreamed the killings for 17 minutes.Not prepared'There are heavy restrictions on who can be in court during Monday's appeal hearing, with only counsel, media and court officials allowed.Families and friends of those killed or wounded in the attacks have been invited to watch proceedings in Christchurch remotely by video with a one-hour delay.Members of the public are also able to watch the hearing by video link with a one-hour delay at a separate courtroom in Wellington.Entry to the court, which stands opposite New Zealand's main government building, the Beehive, is only permitted if people surrender their cellphones.Aya Al-Umari, whose brother Hussein was killed by Tarrant inside Linwood mosque, told Christchurch's The Press newspaper she had thought "this is the end of it" when Tarrant was sentenced.Little did you know that you are allowed to do this six years later. I was not prepared to do this," she The hearing is being held before three Court of Appeal judges.In most Court of Appeal hearings the judges reserve their decision to be published at a later date, meaning a verdict is unlikely this week.

FBI claims not enough evidence to prove Jeffrey Epstein was running a sex trafficking ring, files show

CAIRO. (Agency)

The FBI pored over Jeffrey Epstein's bank records and emails. It searched his homes. It spent years interviewing his victims and examining his connections to some of the world's most influential people.But while investigators collected ample proof that Epstein sexually abused underage girls, they found scant evidence the well-connected financier led a sex trafficking ring serving powerful men, an Associated Press review of internal Justice Department records shows.

Videos and photos seized from Epstein's homes in New York, Florida and the Virgin Islands didn't depict victims being abused or implicate anyone else in his crimes, a prosecutor wrote in one 2025 memo.

An examination of Epstein's financial records, including payments he made to entities linked to influential figures in academia, finance and global diplomacy, found no connection to criminal activity, said another internal memo in 2019.

While one Epstein victim made highly public claims that he "lent her" to his rich friends, agents couldn't confirm that and found no other victims telling a similar story, the records said.Summarizing the investigation in an email last July, agents said "four or five" Epstein accusers claimed other men or women had sexually abused them. But, the agents said, there "was not enough evidence to federally charge these individuals, so the cases were referred to local law enforcement."The AP and other media organizations are still reviewing millions of pages of documents, many of them previously confidential, that the Justice Department released under the Epstein Files Transparency Act and it is possible those records contain evidence overlooked by investigators.

But the documents, which include police reports, FBI interview notes and prosecutor emails, provide the clearest picture to date of the investigation — and why U.S. authorities ultimately decided to close it without additional charges.Dozens of victims come forward

The Epstein investigation began in 2005, when the parents of a 14-year-old girl reported she had been molested at the millionaire's home in Palm Beach, Florida.

Police would identify at least 35 girls with similar stories: Epstein was paying high school age students USD 200 or USD 300 to give him sexualized massages.fter the FBI joined the probe, federal prosecutors drafted indictments to charge Epstein and some personal assistants who had arranged the girls' visits and payments. But instead, then-Miami U.S. attorney Alexander Acosta struck a deal letting Epstein plead guilty to state charges of soliciting prostitution from an underage girl. Sentenced to 18 months in jail, Epstein was free by mid-2009.

What to know about Jimmy Lai's Hong Kong journey from media mogul and activist to convict

HONG KONG. (Agency)

To his supporters, former Hong Kong media mogul Jimmy Lai is a fighter for democracy. To the government, he is a traitor to his motherland.The 78-year-old outspoken critic of China's ruling Communist Party was sentenced Monday to 20 years in prison for conspiring to commit sedition and collude with foreign forces.Observers say his trial came to symbolize a crackdown that began in 2020 on press and other freedoms that has changed Hong Kong, the former British colony that returned to China's control in 1997.The Hong Kong government insists Lai's case has nothing to do with press freedom, but instead is an example of righteousness upheld by the law.

A migrant from mainland China, he made a fortune in the garment industry in Hong Kong and later founded the Apple Daily newspaper, where he

wrote articles criticizing the Chinese and Hong Kong governments for limiting freedoms. The publication eventually was shuttered and his words became trial evidence.

Here is what to know about his unusual journey to political activism that has ended, at least for the moment, in prison.

A stowaway founds a clothing giant

Lai was born in 1947 in the southern Chinese city of Guangzhou, once known as Canton, two years before the communists came to power.

He was just 12 when he stowed away on a fishing boat to Hong Kong, about 135 kilometers (84 miles) from Guangzhou. Like many other Chinese of that era, Lai hoped for a better life in the British colony. Working as a child laborer in a glove factory served as his introduction to the garment industry.In 1981, he founded Giordano, an affordable casual clothing chain that has grown into an international brand with 1,600 retail outlets in 30 countries, according to its website.

Thailand's Anutin rides wave of nationalism to election victory

BANGKOK. (Agency)

Thailand's caretaker premier Anutin Charnvirakul was preparing for coalition talks Monday after his conservative Bhumjaithai Party surged to a stunning election victory on a wave of nationalism.

The pro-military and pro-monarchy party had its best electoral performance ever in polls that took place after border clashes with Cambodia during two rounds of deadly fighting last year.But Anutin, the scion of a construction dynasty, will need to tackle anaemic economic growth and manage fallout over multibillion-dollar cyberscam networks operating from the region.

"Thailand will move like it moved in the past three months. We will see nationalism, a strong position on Cambodia and economic policies. Nothing changes," said Virot Ali, politics lecturer at Thammasat University.

Bhumjaithai was forecast by local media to have won almost 200 seats in Sunday's vote, well ahead of others but short of an outright majority in the 500-member lower house.The reformist People's Party trailed with around 120 seats, while Pheu Thai -- the party of jailed former prime minister Thaksin Shinawatra -- came in third.

Voters appeared to turn their backs on the two parties, with their vote shares diving compared to the last poll in 2023, according to preliminary results from the election commission.Pheu Thai had its worst showing since Thaksin founded his political dynasty, after his daughter Paetongtarn was felled as prime minister over her handling of the Cambodia border dispute.Thaksin is serving a one-year prison sentence for corruption in office, but many observers expect him to be released earlier than scheduled alongside a political agreement.

Phone call scandal

Paul Chambers, an associate senior fellow at

ISEAS-Yusof Ishak Institute in Singapore, told AFP that Bhumjaithai achieved victory by "emphasizing its commitment to nationalism and the king".The conservatives also benefitted from the "continuing unpopularity of Pheu Thai" following a leaked phone call in which Paetongtarn referred to Cambodia's former leader Hun Sen as "uncle" and described a Thai military commander as her "opponent".The leak sparked public and political backlash, and she was later dismissed from office by the constitutional court on an ethics complaint.Still, Pheu Thai is seen as a likely coalition partner for Anutin, as they were allies until Bhumjaithai pulled out over the border dispute scandal.Anutin, who took office in September, declined to be drawn Sunday on potential coalition talks, noting the election results remained unofficial."We will wait until it's more clear, and every party has to meet their executive board to discuss the position," he said.Political analyst Napon Jatusripitak expected Bhumjaithai to "move quickly" to form a government in which its interests would prevail.The conflict with Cambodia, which killed scores of people on both sides and displaced around a million altogether, was top of mind for voters.Soon after becoming premier following Paetongtarn's removal, Anutin authorised the armed forces to take whatever action they saw fit on the border.

NEWS BOX

Like Sachin Tendulkar, fast-track Vaibhav Sooryavanshi to Team India: Shashi Tharoor

NEW DELHI. (Agency)

After Vaibhav Sooryavanshi's towering hundred in the U19 World Cup final against England, Congress MP Shashi Tharoor has advocated fast-tracking the prodigious batter into the senior Indian side. Tharoor took to X to state that Vaibhav is a generational talent and drew parallels with legendary Sachin Tendulkar.Sachin, back in the late 1980s, was himself fast-tracked into the Indian team after showing extraordinary potential on the maidans of Mumbai. Vaibhav Sooryavanshi, on the other hand, made his name through age-group cricket before announcing himself in spectacular fashion with a remarkable debut season in the 2025 Indian Premier League.Vaibhav Sooryavanshi deserves to be fast-tracked into higher honours. The last time we had a 14-year-old genius at the crease, his name was Sachin Tendulkar. And we didn't keep him waiting long," Tharoor wrote on X while reacting to an advertisement featuring the young batter.

U19 Final: Vaibhav's Superhuman Innings

Fourteen-year-old Vaibhav Sooryavanshi rose to the occasion for India in the U19 World Cup final. Batting on a testy pitch in Harare, Vaibhav weathered the early spells from

England's fast bowlers before responding with breathtaking shot-making of his own.The left-hander tore into the English spinners around the end of the first powerplay and maintained the momentum for the remainder of his innings. He brought up his century in just 55 balls and soon surged to 175 off 80 deliveries before finally being dismissed.Vaibhav's extraordinary knock propelled India to a record total of 411 in a U19 World Cup final, a target that the Ayush Mhatre-led side went on to defend successfully.

Sachin Tendulkar's Fast-Tracking to Team India

Sachin Tendulkar's rise to the Indian national team remains one of the most remarkable fast-tracks in cricket history. Born in 1973, Tendulkar was just 16 when he was selected for India's tour of Pakistan in 1989, an age when most cricketers are still finding their feet in junior cricket. What set him apart was not only prodigious talent, but an uncommon composure that convinced selectors he was ready for the highest level.

Liverpool's Slot slams referee for Szoboszlai red-card vs City: Where's the rule book

Liverpool boss Arne Slot slammed the match officials after Dominik Szoboszlai's late red card in the chaotic 2-1 defeat to Manchester City at Anfield. Slot instead highlighted Marc Guehi's foul on Mohamed Salah.

NEW DELHI. (Agency)

Liverpool head coach Arne Slot hit out at the match officials after Dominik Szoboszlai was shown a late red card in the dramatic closing stages of Manchester City's 2-1 comeback win over the Reds at Anfield. The defeat dented Liverpool's push for a Champions League spot, while City's victory brought them within six points of Arsenal at the top of the Premier League table.The flashpoint came in stoppage time when Szoboszlai was sent off following VAR intervention. Speaking at the post-match press conference, Slot refused to dwell on the Hungarian's dismissal and instead pointed to an earlier incident involving Mohamed Salah as the bigger talking point.

"That is not the incident we should talk about," Slot said. "Maybe he should have left it for a goal as it is, but if that is the rule that is what we have to accept."If there is any incident we should talk about, it's when Mo Salah is one on one with the goalkeeper. Anyone who has been to this stadium in the last seven or eight years, that is a goal for Salah. Once again, the referee decides not in our favour. They have to do their job."The incident Slot heated up about came when Liverpool appealed for a red card after Marc Guehi pulled down Salah outside the box as the forward surged towards goal. Pawson awarded only a yellow card, with VAR confirming the decision as there was deemed to be a covering defender.

Why did Szoboszlai get a red-card vs City?Szoboszlai's red card arrived in the 90th+10 minute with Liverpool chasing a late equaliser and Alisson Becker pushing upfield. Manchester City substitute Rayan Cherki struck a long-range effort towards an empty net, with Erling Haaland racing clear to retrieve the loose ball.Szoboszlai pulled Haaland back in an attempt to stop him, and while Pawson initially allowed play to continue and awarded the goal, VAR overturned the decision. The goal was disallowed and Szoboszlai was sent off for denial of a clear goalscoring opportunity.

What did Man City and Haaland say?Haaland admitted he felt sympathy for the Liverpool midfielder, suggesting the outcome was harsh."Of course, the referee had to follow the rules but this will give him three games," Haaland said. "In the end I feel bad for him because he gets three games."Just give the goal, don't give a red card. Simple as that. It's the rules and how it is."Manchester City manager Pep Guardiola also questioned the decision-making, arguing the officials could have simply allowed the goal to stand."We won the game and now Szoboszlai cannot play," Guardiola said. "I know he pulled him, but many pulls are there in a game where the referee says 'play on', 'play on', 'play on'?

"So give a goal, 3-1, Szoboszlai can play and we are happy."City were also awarded a penalty after Alisson clattered into Matheus Nunes, a call that was again checked and upheld by VAR.Ultimately, City's 2-1 win reshaped the title race at the top, while Liverpool's loss leaves them sixth, five points off the Champions League places.

ICC meeting with Pak done, Shehbaz Sharif to decide on India match: Report

NEW DELHI. (Agency)

The Pakistan Cricket Board is reportedly set to clarify its stance on the proposed boycott of its T20 World Cup 2026 match against India within the next 24 hours, following a marathon meeting with senior ICC officials in Lahore. With the mega India vs Pakistan, T20 World Cup group-stage match on February 15 just around the corner, the issue has quickly turned into one of the biggest talking points in world cricket.The discussions took place at Lahore's Gaddafi Stadium and stretched beyond five hours, involving PCB chairman Mohsin Naqvi, ICC Deputy Chairman Imran Khwaja, and Bangladesh Cricket Board president Aminul Islam. The urgency is obvious, with the ICC keen to avoid a situation where the tournament's most high-profile fixture is left hanging in uncertainty.

According to reports, the PCB is now expected to consult Pakistan's federal government before taking a final call. Officials believe the next 24 hours could prove decisive, as the board weighs both political direction and the wider consequences of stepping away from cricket's most watched rivalry. Naqvi is also likely to address a press conference today, with clarity expected soon after.What was the ICC-PCB meeting about?

At the heart of the Lahore meeting was Pakistan's decision to skip its scheduled group match against India on February 15 in

Colombo. The boycott announcement, made on February 2 with the World Cup less than a week away, escalated tensions and forced the ICC into urgent negotiations.

Bangladesh's presence in the talks added another layer. BCB President, Aminul Islam, had landed in Lahore just hours before the meeting, signalling that Bangladesh and Pakistan have found common ground as the ICC works to broker a compromise. Sources told India Today that both boards have aligned their positions during these discussions.

The ICC's primary focus has been to prevent the situation from spiralling into a full-blown crisis, one that could impact scheduling, governance, and the commercial structure of the tournament.

Naqvi, meanwhile, is set to brief Prime Minister Shehbaz Sharif on the matters discussed, underlining just how significant the decision has become beyond cricket alone.

Why does ICC want an IND vs PAK match at T20 World Cup?

Simply put, no fixture in cricket comes close to India vs Pakistan in terms of global attention and financial value. It is the sport's biggest revenue driver, powering broadcast rights, sponsorship deals, advertising interest, and worldwide viewership.Broadcasters pay a premium largely because marquee games like this are guaranteed audience magnets. If Pakistan were to withdraw, the ICC's broadcast package would immediately lose value, creating a knock-on effect across the tournament's finances.The effect will stretch out in problematic extent, as reduced revenues would eventually affect annual payouts to member boards, including Pakistan, Bangladesh, and even India.With the clock ticking and the World Cup already underway, the next 24 hours could shape whether cricket's fiercest rivalry takes centre stage or becomes the biggest absentee of the tournament.

Lindsey Vonn breaks leg in downhill crash at Winter Olympics, in stable condition at hospital

CORTINA D'AMPEZZO. (Agency)

Lindsey Vonn's defiant bid to win the Winter Olympic downhill at the age of 41, on a rebuilt right knee and a badly injured left knee, ended Sunday in a frightening crash that left her with a broken leg and saw her taken to safety by a rescue helicopter for the second time in nine days.Vonn lost control within moments of leaving the start house, clipping a gate with her right shoulder and pinwheeling down the slope before ending up awkwardly on her back, her skis crisscrossed below her and her screams ringing out soon after medical personnel arrived. She was treated for long, anguished minutes as a hush fell over the crowd waiting far below at the finish line.She was strapped to a gurney and flown away, possibly ending the skier's storied career. She was taken to a clinic in Cortina, then transferred to a larger hospital in Treviso, a two-hour drive to the south.

She was being "treated by a multidisciplinary team" and "underwent an orthopedic operation

to stabilise a fracture reported in her left leg," the Ca' Foncello hospital said in a statement. The U.S. Ski Team said Vonn was "in stable condition and in good hands with a team of American and Italian physicians."

"She'll be OK, but it's going to be a bit of a process," said Anouk Patty, chief of sport for U.S. Ski and Snowboard. "This sport's brutal and people need to remember when they're watching (that) these athletes are throwing themselves down a mountain and going really, really fast."Breezy Johnson, Vonn's teammate, became only the second American woman to win the Olympic downhill after Vonn did it 16 years ago. The 30-year-old Johnson held off Emma Aicher of Germany and Italy's Sofia Goggia on a bittersweet day for the team.

March of the underdogs: How associate nations are adding flair to World Cup

NEW DELHI. (Agency)

On the field, it came down to a last-ball shoot out. In our minds, it came down to the oldest rivalry in storytelling.On Sunday, England were defending 184 against Nepal in their opening T20 World Cup match. The Himalayan Kingdom needed six off the last ball. Sam Curran had the ball. Lokesh Bam had the bat. Karan KC was at the other hand.Sam vs Bam. David vs Goliath. Wham Bam, Good night Sam? The Wankhede crowd held its breath, and a question.In 2024, David had defied expectations. Nepal had lost to South Africa by just one run. Will the underdog win today?The signs till the last over were promising. Jofra Archer, Luke Wood and Adil Rashid had been beaten out of shape by Nepal's batters. Just 10 were needed. But Curran's low yorkers held their shape.When the final delivery thudded into the fielder's hands at deep cover, the entire

Wankhede could hear England exhale. England escaped by four runs, the scoreboard said defeat. But the stadium, the analysts, and the cricketing world knew better.

Something had shifted.

That over, those six balls, was the moment the T20 World Cup stopped being a tournament about favourites and became a story about disruption.THE DISRUPTION

The first week of the T20 World Cup has shattered one of cricket's oldest assumptions: that there are minnows in international cricket. As Namibia captain Gerhard Erasmus declared, it is high time the tags Associate and minnows were removed.In a tournament featuring 10 Associate nations, teams like Nepal, USA, and Netherlands have delivered performances that blur the line between established powers and emerging forces. All of them came within striking distance against England, India and Pakistan, losing only because of dropped catches, or defeat-defying brilliance of Curran and Suryakumar Yadav.

ROM YAWN TO YARN

When the tournament draw was announced, featuring 10 Associate nations.

Italy opt to bowl against Scotland on T20 World Cup debut

NEW DELHI. (Agency)

Italy skipper Wayne Madsen won the toss and opted to bowl against Scotland in a T20 World Cup match at the Eden Gardens here on Monday.Italy are making their World Cup debut and Madsen said his team was looking to "enjoy" the contest and "express themselves" on the big stage.

Scotland captain Richie Berrington made one change to the side that lost to the West Indies in the opener, bringing in Brad Wheal in place of Safyaan Sharif.Teams: Italy: Anthony Mosca, Justin Mosca, JJ Smuts, Wayne Madsen (c), Harry Manenti, Ben Manenti, Grant Stewart, Gian-Piero Meade (wk), Marcus Campopiano, Crishan Kalugamage, Ali Hasan.

Scotland: George Munsey, Michael Jones, Brandon McMullen, Richie Berrington (c), Tom Bruce, Matthew Cross (wk), Mark Watt, Michael Leask, Oliver Davidson, Brad Wheal, Brad Currie.

Who is Dhakshineswar Suresh India's Davis Cup star who left Netherlands stunned

Dhakshineswar Suresh announced himself as India's newest Davis Cup hero, sweeping all three rubbers against the Netherlands. The 25-year-old's stunning weekend powered India into Qualifiers Round 2 for the first time since 2019.

New Delhi, (Agency)

Dhakshineswar Suresh was not supposed to be the headline act of India's Davis Cup weekend. Tennis, after all, loves its rankings, its familiar names, its predictable scripts. And yet, by Sunday evening, the 25-year-old had flipped the entire tie on its head and walked away as the player everyone was talking about.

India's World Group I clash against the Netherlands had the feel of a tricky test, the kind of tie where you hope to hang in and maybe steal it late. Instead, it turned into a stage for one man's breakout. Suresh, known affectionately as "DK", produced a performance that belonged to the Davis Cup's greatest hits.He won all three rubbers he played. Both singles matches, plus the doubles alongside Yuki Bhambri. That clean sweep powered India to a memorable 3-2 victory and booked their place in Qualifiers Round 2, a milestone the team has not reached since the Davis Cup adopted its new format in 2019.He makes us feel mortal," Bhambri said about Suresh after the crowning moment.The defining moment arrived in the decisive fifth rubber. With the tie on a knife-edge, DK faced Guy de Ouden and played with remarkable calm, taking it 6-4, 7-6(4). When the final forehand landed, he dropped flat on his back, equal parts exhausted and relieved, before being mobbed by teammates who knew they had just witnessed something special.Who is Dhakshineswar Suresh?

So who exactly is this new Indian Davis Cup hero who left the Netherlands stunned?

Dhakshineswar Suresh is a 6-foot-5 right-hander from Madurai, Tamil Nadu, and his rise has taken a slightly different route

compared to the traditional Indian tennis pathway. While India's Davis Cup history often brings up images of crafty volleyers and soft-handed net play, DK looks every bit like a modern power-baseliner.His game is built around a booming serve, heavy forehands, and the ability to dictate rallies from the back of the court. When he finds his rhythm, the angles he creates off his first delivery can make returning feel like a guessing game.What makes his story even more interesting is where he was shaped. DK is very much a product of the American college tennis system, a route that has quietly become a launching pad for several emerging players. He first made his mark at Georgia Gwinnett College, winning multiple NAIA titles and developing a reputation as someone who thrives in big-match situations.

What Dhakshineswar Suresh's early career looked like

From there, he stepped up to NCAA Division I tennis with Wake Forest University, one of the strongest programmes in the United States. The grind of college tennis, with its relentless schedule and team-driven pressure, helped sharpen both his physical base and his temperament.

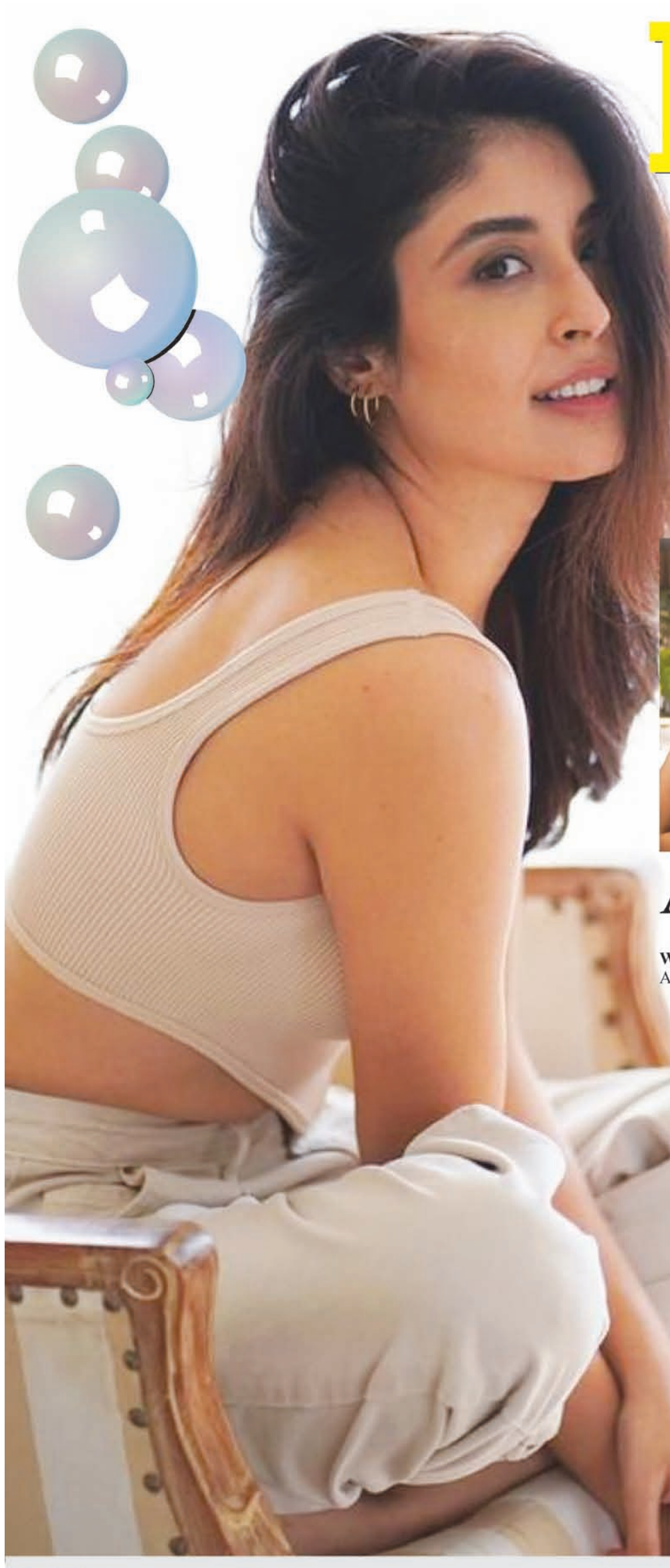

Kritika Kamra

And Gaurav Kapur To Get Married In March 2026; Wedding Details Inside

Actors Kritika Kamra and Gaurav Kapur are reportedly all set to take a big leap in their relationship. After making their romance public in December, the couple is now said to be planning their wedding, with 2026 shaping up to be a milestone year for them.According to sources, the duo is in a strong, happy space and has decided it is time to formalise their relationship.

Wedding Likely Around March–April 2026

A source close to the couple told Hindustan Times that Kritika and Gaurav are looking at a wedding around the end of March or early April, "Kritika and Gaurav are in a happy space together and ready to take their relationship to the next level. They are planning to tie the knot in March end or in the first week of April," the source said.

The wedding is expected to take place in Mumbai, keeping things close to home for both their families and inner circle.

Mumbai Reception on the Cards

While the finer details of the wedding celebrations are still being worked out, an industry reception is already on the agenda, "They are still finalising the details of the functions, but they will definitely host a reception for their industry friends in Mumbai itself," the source added.

The 'Insta Official' Moment That Started It All

Kritika and Gaurav first confirmed their relationship in December when Kritika shared a series of pictures from what appeared to be a cosy breakfast date. The understated caption, "Breakfast with," was enough to send fans into a frenzy.

The post drew warm reactions from several industry friends, including Pooja Gor, Anup Soni, Angad Bedi, Nakuul Mehta and Drashti Dhami, who flooded the comments section with congratulatory messages.

Ringing in 2026 Together

The couple welcomed the New Year with a getaway to Jaisalmer, further fuelling wedding buzz. Kritika shared glimpses from the trip and captioned the post, "Fell into '26 nicely," subtly hinting at the new chapter ahead.

Natasa Stankovic

Trolled For Dancing At College Fest; Social Media Defends Actress

Actor-model Natasa Stankovic, who made headlines following her divorce from ace cricketer Hardik Pandya, is back in the limelight after a video of her dancing at a college fest went viral on social media. The video has invited widespread trolling for Natasa Stankovic, with many dropping derogatory remarks against her. Meanwhile, a section of social media was seen urging people not to target her.

The video shows Natasa dancing in a black-and-white outfit at Pillai University's college fest. As the video went viral, people started trolling Natasa. One said, "After divorcing Hardik, she became so unemployed that she had to dance at colleges just to live." Another shared, "Lol, she already grabbed 70% of Hardik's hard-earned assets." A third user commented, saying, "Breakup nahi, full downgrade arc."

People defend Natasa

While trolls tried to bully Natasa, many came out in support of her. One wrote, "It's called living the way you like. Also, it's better than staying in a toxic relationship. No job is big or small. Stop shaming someone just because they are not as successful as their husband or boyfriend. Same goes for girls." Another user shared, "So what? She is trying to earn a living, and people have a problem with that as well now?" A third user commented, "She is living happily and not seeking media attention. That is important. She is not playing the victim card."One user, while defending Natasa, shared, "Show some respect, man. The girl isn't always wrong. Stop blaming her every time." Another wrote, "After the divorce, instead of sitting at home or playing the victim card, Natasha Stankovic chose to work with dignity. Dancing at colleges, events, anywhere she's respected, that's called self-respect and independence, not unemployment."

About Natasa and Hardik

Natasa Stankovic married Hardik Pandya in May 2020 and welcomed their son, Agastya, in the same year. The pair renewed their vows in 2023 but later the same year decided to part ways. Even after parting ways, Natasa and Hardik have continued to maintain a dignified relationship focused on co-parenting Agastya. While they no longer share a home or marriage, sources indicate that both remain united in ensuring stability and happiness for their young son.

Pati Patni Aur Woh Do Postponed: Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan's Film Will Now Hit Theatres In May 2026

There has been a lot of buzz around 'Pati Patni Aur Woh Do' ever since it was officially announced. The comedy-drama, starring Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Rakul Preet Singh, and Wamiqa Gabbi, is the highly anticipated sequel to the 2019 film Pati Patni Aur Woh. Last year, the makers revealed that the film would release in theatres on March 4, 2026, during Holi. However, the film's release has now been postponed. The makers have announced a new release date, sharing that Pati Patni Aur Woh Do will now hit theatres on May 15, 2026.

Pati Patni Aur Woh Do Postponed

Trade analyst Taran Adarsh took to X (formerly Twitter) to announce the new release date of Pati Patni Aur Woh Do. "AYUSHMANN KHURRANA – SARA ALI KHAN – WAMIQA GABBI – RAKUL PREET SINGH: 'PATI PATNI AUR WOH DO' GETS A NEW RELEASE DATE… Welcome to the world of #PrajapatiPandey… #AyushmannKhuranna, #SaraAliKhan, #WamiqaGabbi, and #RakulPreetSingh team up for #PatiPatniAurWohDo. Directed by #MudassarAziz, the film will now hit cinemas on 15 May 2026. Produced by #BhushanKumar and #RenuRaviChopra, with #JunoChopra as the creative producer," read the post.

Recently, Bollywood Hungama reported that the film will not release on March 4 because the post-production is not yet complete and a song also remains to be shot. The report states that the makers did not want to rush the process and wanted to devote time and effort into ensuring that the final product turns out to be entertaining as well as enticing for the audience.

The film marks director Mudassar Aziz's return to the franchise after the first instalment, which featured Kartik Aaryan, Bhumi Pednekar, and Ananya Panday. This time, the story promises a fresh twist with a new ensemble and more outrageous comic situations.

Last year in October, the makers dropped the first poster of Pati Patni Aur Woh Do, introducing Ayushmann as Prajapati Pandey and teasing a world filled with love, laughter, and inevitable marital confusion.Mark your calendars for a joyride of emotions as Pati Patni Aur Woh Do is all set to hit the big screen on 15th May 2026!

'It Was The Perfect Moment': Priya Banerjee Recalls Prateik Smita Patil's Dreamy Wedding Proposal

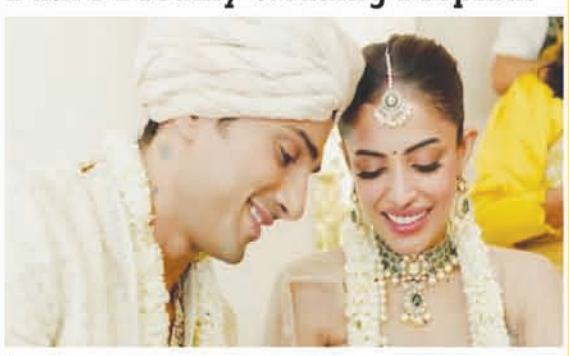

Prateik Smita Patil and Priya Banerjee will mark their first wedding anniversary this year on Valentine's Day, and as the couple gears up for a grand celebration, they recalled their dreamy proposal on Propose Day today. Priya got her dreamy proposal at midnight on the eve of Prateik's birthday.Speaking to HT, Prateik recalled, "I had planned to propose to Priya at the stroke of midnight on the eve of my birthday. But we had some work the next day, for which we had to leave early in the morning, so if I had done that, we wouldn't have got time to enjoy the moment." He added, "Then, two days before, on a Sunday morning, I was sitting on my 'throne' in the bathroom, where I get some of my best ideas. I realised that we had the whole day to ourselves, and it was the perfect day to propose."

Speaking about the day she finally got her proposal, November 26, Priya recalled, "It was 8 am, and I saw Prateik crying in the corner, and I was like, what has happened? I was lying in bed with our dog, and Prateik suddenly came next to the bed and proposed to me. He was so emotional that I didn't even understand the first question he asked me."

Priya further continued and shared that it was a perfect moment for her and said, "He went down on his one knee while in his boxers, but it was the perfect moment, as we also had our dog there, who just started wagging his tail. It was a celebration with the three of us."

After dating each other for a long time, Prateik and Priya decided to take their relationship to the next level on the day of love, i.e., Valentine's Day. The couple got married in an intimate wedding ceremony held at Prateik's late mother Smita Patil's house in Bandra, Mumbai, on February 14, 2025. Taking to their social media, the newly married couple shared a series of heartwarming pictures, perfectly capturing the warmth, love, and togetherness of the people who gathered to celebrate their bond. In a post captioned "I'll marry you in every lifetime #priyaKAprateik," Prateik and Priya shared their first-ever pictures as a married couple.